

डिलेवरी के नाम पर सिविल हॉस्पिटल में जारी है वसूली

मामला सिविल से शुरू हुआ और सारंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर पर मामला हुआ दर्ज

माही की गूंज, पेटलावद।
राकेश गेहलोत

स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति किस कदर खराब हो चली है कि अब आम आदमी सरकारी स्वास्थ्य व सुविधाओं के बदले निजी हॉस्पिटलों की ओर रुख करने लगा है। असुविधाओं के बीच मरीजों और उनके परिवारजनों को निजी हॉस्पिटलों की तरह इलाज के नाम पर वसूली और निजी मेडिकलो से दवाइयां मंगवाई जा रही है। सिविल हॉस्पिटल पेटलावद में डिलेवरी के नाम पर वसूली का पहला मामला नहीं है, पूर्व में भी कई बार शिकायतें और ऑडियो-वीडियो सामने आ चुके हैं। लेकिन हर बार शिकायतों या पीड़ित पर दबाओ बना कर आपसी समझौता करवा कर मामला दबा दिया जाता है। इस बार कुछ ऐसा नहीं हुआ और मामला ऐसा प्रचारित हुआ कि मामला अपहरण, मारपीट और पुलिस प्रकरण तक पहुंच गया।

डिलेवरी के नाम पर पेसो की मांग,
विडियो वायरल

गत दिनों पेटलावद सिविल में डिलेवरी के लिए गई महिला के पति अर्जुन गरवाल निवासी बोडईता से स्टॉफ नर्स दिया सोलंकी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें स्टॉफ नर्स डिलेवरी के लिए पेसो की मांग करती नजर आ रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी मामला रफा-दफा करने की कोशिश की गई। अगले ही दिन सोशल मीडिया पर एक स्टॉप्प वायरल होता है जिसमें वीडियो बना कर वायरल करने वाले अर्जुन गरवाल द्वारा डिलेवरी के लिए किसी प्रकार की मांग नहीं होने के संदर्भ में शपथ-पत्र दिया गया था। जब इस शपथ-पत्र की सच्चाई सामने आई तो चौका देने वाले खुलासा हुए।

पूर्व बीएमओ पर लगा युवक को
अपहरण कर धमकाने का आरोप,
आदिवासी संगठनों ने दर्ज
करवाया मामला

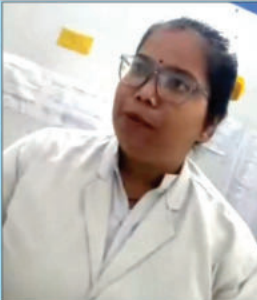
उक्त प्रकरण रोज नए-नए परिवर्तन के साथ सामने आने लगा। पेसो की मांग के वीडियो को गलत बताने के बाद ,स्टॉप्प सामने आया और जब आदिवासी संगठन के लोग इस मामले की तह तक गए तो पता लगा कि, सारंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ पूर्व बीएमओ पेटलावद सुरेश कटारा पीड़ित पक्ष को डराने धमकाने, मारपीट कर अपहरण कर जबरन स्टॉप्प लिखवा कर समझौता करने का दबाओ बनाने का मामला सामने आया। आदिवासी संगठनों के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर इस प्रकार के आरोपों की पुष्टि की है कि, उससे डाक्टर कटारा और उसके झुंडवर ने जबरन डरा-धमका कर समझौते का स्टॉप्प पर हस्ताक्षर करवाया। जिसके बाद आदिवासी संगठन के लोग डाक्टर कटारा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए सारंगी चौकी पर पहुंच गए। काफी देर की बहस बाजी के बाद आखिर पुलिस ने डाक्टर कटारा और अन्य के विरुद्ध कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।

सिविल का मामला आखिर सारंगी कैसे
पहुंचा, डाक्टर कटारा ने क्यों दिखाई रुचि

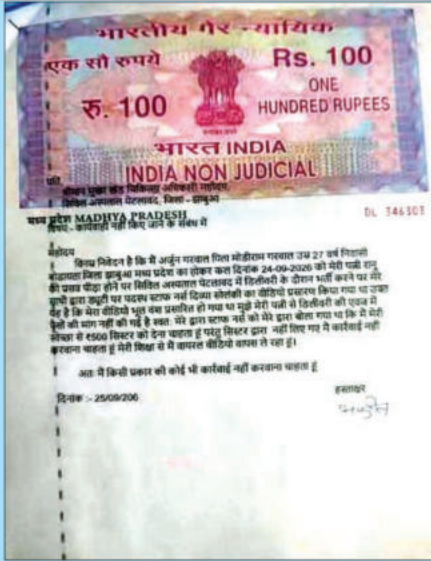
पूरे मामले में चर्चा का विषय बना हुआ है कि, पेसो की मांग और पूरा मामला सिविल हॉस्पिटल पेटलावद का था फिर सारंगी के डॉक्टर कटारा की इंट्री आखिर क्यों हुई। जबकि पूरे मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं था। अब चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि दूसरे के मामले



पीड़ित को धमका कर मामले में समझौता करवाने वाले पूर्व बीएमओ सुरेश कटारा।



डिलेवरी के लिए पेसो की मांग करने वाली रटाफ नर्स दिया सोलंकी।



वीडियो वायरल करने वाले अर्जुन गरवाल का समझौते का शपथ-पत्र।

में टांग क्यों फसाई गई वो भी दादागिरी पूर्वक। वही मामला दर्ज होने के बाद भी धमकियों का दौर चल रहा है।

जयस संगठन के जिला प्रभारी प्रकाश डामर ने बताया कि, शिकायतकर्ता पीड़ित को पुलिस सुरक्षा दी जाए क्योंकि वसूली के इस खेल में पूरी गैंग लगी हुई है जो अपने ऊपर आने वाली बात को निपटाने के लिए किसी भी हद तक चले जाने को तैयार रहते हैं। जयस संगठन के जिला अध्यक्ष विजय डामर ने मांग की है कि, सिविल हॉस्पिटल पेटलावद में लगातार इलाज के नाम पर वसूली ,समय पर डाक्टरों के अनुपलब्धता ,निजी मेडिकलो से दवाइयां मंगवाने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। जिला कलेक्टर और जिला स्वास्थ्य अधिकारी मामले का संज्ञान लेकर व्यवस्था में सुधार करवाए अन्यथा संगठन को सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस विषय में डॉक्टर सुरेश कटारा का पक्ष जानने की कोशिश की गई लेकिन उनका फोन लगातार बंद ही आया।



डॉक्टर कटारा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने के लिए सारंगी चौकी पर पहुंचे आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता।

स्तदान शिविर: 121 यूनिट रक्त संग्रहित

माही की गूंज, झाबुआ।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झकनावदा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नागरिकों एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए रक्तदान किया, जिसके माध्यम से कुल 121 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट रक्तदान शिविर में पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा उन्हें प्रमाण-पत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया।

छात्रों ने जनसहयोग से बदली विद्यालय की तस्वीर प्रत्येक संकुल में कम से कम एक विद्यालय को जनसहयोग से विकसित करने के निर्देश

माही की गूंज, झाबुआ।

कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने बालिका विद्यालय झकनावदा की निरीक्षण कर विद्यालय में जनसहयोग से विकसित की गई सुविधाओं एवं शैक्षणिक वातावरण का अवलोकन किया। विद्यालय को बेहतर स्वरूप देने के लिए एकीकृत पीएमश्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झकनावदा के पूर्व छात्रों द्वारा मिलकर जनसहयोग से किए गए प्रयासों की कलेक्टर ने विशेष सरहना की।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉ. भरसट ने विद्यालय के कक्षों, उपलब्ध शैक्षणिक संसाधनों, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर संबंधी सुविधाओं, पेयजल व्यवस्था, पुस्तकालय एवं अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि पूर्व छात्रों और स्थानीय समुदाय की सहभागिता से किसी शासकीय विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करना जनभागीदारी का अच्छा उदाहरण है।

विद्यालय को विकसित करने की इस पहल में शिक्षक हेमन्त कुमार जोशी की भूमिका को भी कलेक्टर ने सराहना की। श्री जोशी द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए प्रारंभ किए गए प्रयासों के साथ समय-समय पर पूर्व विद्यार्थियों, ग्रामीणों एवं समाजसेवियों का सहयोग जुड़ता गया। सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की गई हैं।

कलेक्टर डॉ. भरसट ने कहा कि शासकीय विद्यालयों के विकास में पूर्व विद्यार्थियों एवं स्थानीय समुदाय की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि झकनावदा में किए गए इस प्रयास को मॉडल के रूप में लेते हुए जिले के प्रत्येक संकुल में कम से कम एक विद्यालय को इसी प्रकार जनसहयोग एवं पूर्व छात्रों की सहभागिता से विकसित किया जाए।



नशा तस्करों की 3.78 करोड़ की संपत्ति फीज

माही की गूंज, रतलाम। अवैध कमाई से अर्जित नशा तस्करों की संपत्तियों पर शिकंजा कसते हुए थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा और बिलपांक पुलिस द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर सफेमा/ एनडीपीएस न्यायालय सक्षम प्राधिकारी मुंबई ने दो अलग-अलग प्रकरणों में करीब 3.78 करोड़ रुपये की संपत्तियों के फ्रीजिंग आदेशों की पुष्टि की है। जावरा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने 29 जून 2017 को रईस खान मेवाती निवासी ग्राम उमटपालिया को गिरफ्तार कर 1623.300 किलो डोडाचूरा जप्त

किया था। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस जावरा ने उसे 15 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। रईस करीब 10 से 15 वर्षों से मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में तस्करों में लिस रहा। 22 अगस्त को जारी फ्रीजिंग आदेश के बाद सक्षम प्राधिकारी ने उमटपालिया स्थित तीन कृषि भूमियों की करीब 48 लाख रुपये की संपत्ति की फ्रीजिंग की पुष्टि की। इनमें सर्वे नंबर 102126/1/1/1, 102126/1/1/2 और

102126/2/1 की कृषि भूमि शामिल है।

81 किलो डोडाचूरा के साथ गिरफ्तार किया था

दूसरे प्रकरण में बिलपांक पुलिस ने ग्राम धराड़ निवासी दिनेश पुत्र गिरधारीलाल को 81 किलो डोडाचूरा के साथ 28 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस रतलाम ने दिनेश को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख

रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस को आरोपित और उसके परिवार का कोई ज्ञात वैध आय स्रोत नहीं मिला। 29 अगस्त को जारी फ्रीजिंग आदेश के तहत सक्षम प्राधिकारी ने पांच संपत्तियों की फ्रीजिंग की पुष्टि की है। इनमें सर्वे नंबर 1582/ 5 (एस) की 0.62 हेक्टेयर, 1627/ 3 (एस) की 0.54 हेक्टेयर, 1582/ 1 (एस) की 0.62 हेक्टेयर और 1732/ 2 (एस) की 0.42 हेक्टेयर कृषि भूमि तथा 111.48 वर्गमीटर का आवासीय मकान शामिल है।

माही-नर्मदा का मिलन ही आने वाले जल संकट से निपटने के एक मात्र हल

माही डेम में नर्मदा का पानी डालने की मांग, किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, पेटलावद।

इस बार मानसून में हुई कम बारिश ने किसानों सहित आम आदमी को भी चिंता में डाल दिया है। क्षेत्र में इस वर्ष मानसून के दौरान अपेक्षित वर्षा नहीं होने से जलसंकट की चिंता गहराने लगी है। कम वर्षा का असर खेतों के साथ-साथ तालाबों, जल स्रोतों और माही डेम में सिंचाई और पेयजल की संभावित समस्या को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों सहित आमजन ने माही डेम में नर्मदा का पानी डालने की मांग उठाई है। इस संबंध में यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेटलावद को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र की जल समस्या के स्थायी समाधान की मांग की।

ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि, वर्तमान में क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण किसान और आमजन भविष्य में जलसंकट को लेकर चिंतित हैं। वर्षा की कमी के चलते खेतों में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता को लेकर भी किसानों के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों और अन्य जल स्रोतों में भी अपेक्षित जलभराव नहीं होने से आने वाले दिनों में इसका असर पेयजल और पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता पर पड़ने की आशंका जताई गई है।

22 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को मिलता है सिंचाई का लाभ

भारतीय किसान यूनियन ने ज्ञापन में माही डेम को

क्षेत्र की कृषि व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला बताया। यूनियन के अनुसार माही डेम से करीब 22 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती है। इस क्षेत्र में सोयाबीन, मक्का, उड़द, चना, गेहूं और कपास सहित विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। किसानों के लिए माही डेम का पानी खेती के लिहाज से महत्वपूर्ण है और वर्षा कम होने की स्थिति में इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। किसानों का कहना है कि, क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में खेती के साथ पशुपालन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पेटलावद तहसील में प्रतिदिन करीब 28 से 30 हजार लीटर दूध का उत्पादन होने का उल्लेख ज्ञापन में किया गया है। ऐसे में पर्याप्त पानी की उपलब्धता खेती के साथ पशुपालन के लिए भी जरूरी है।

नगर सहित कई गांवों की पेयजल व्यवस्था भी माही पर निर्भर

ज्ञापन में माही डेम को केवल किसानों की सिंचाई का साधन ही नहीं, बल्कि क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था से भी जोड़ते हुए बताया है कि, झाबुआ जिले के कई गांवों में पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। वहीं पेटलावद नगर की पेयजल व्यवस्था में भी माही डेम की महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारतीय किसान यूनियन संघ ने बताया कि, माही डेम से चौर बावली स्थित डेम में पानी पहुंचाया जाता है। जिसके बाद पेटलावद नगर में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। ऐसे में कम वर्षा के कारण माही डेम में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं रहा तो भविष्य में इसका असर किसानों के साथ आमजन की पेयजल व्यवस्था पर भी

पड़ सकता है।

नर्मदा-माही परियोजना से जलसंकट दूर करने की मांग

किसान यूनियन ने सरकार से मांग की है कि, नर्मदा-माही परियोजना के तहत नर्मदा का पानी माही डेम में पहुंचाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। यूनियन का कहना है कि, यदि नर्मदा का पानी माही डेम में पहुंचाया जाता है तो इससे क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है। ज्ञापन में किसानों ने सरकार से इस मांग पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। किसानों का कहना है कि वर्तमान में कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए भविष्य के जलसंकट से निपटने के लिए समय रहते स्थायी जलस्रोत और जल प्रबंधन पर काम किया जाना जरूरी है।

सुनवाई नहीं तो बड़ा जल संकट खड़ा होने की आशंका

किसान यूनियन के जिला महासचिव जितेंद्र पाटीदार ने

ग्राम स्वराज बचाने सरपंचो का भोपाल कूच



माही की गूंज, रानापुर/कुंदनपुर।

गांव की सरकार के जिम्मेदार मुखियाओं ने अब राजधानी का रुख किया है। रानापुर जनपद क्षेत्र के सरपंच-ग्राम स्वराज अधिकार बचाओ यात्रा-में शामिल होकर भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पहुंचे। पंचायतों के अधिकार और ग्राम स्वराज की व्यवस्था को लेकर सरपंचों की यह मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही है।

गांव की जनता विकास की उम्मीद लेकर सरपंचों की ओर देखती है। सड़क से लेकर नाली, पानी से लेकर अन्य मूलभूत सुविधाओं तक की जिम्मेदारी पंचायतों के कंधों पर है। लेकिन जब इन्हीं पंचायत प्रतिनिधियों को अपने अधिकारों की बात रखने राजधानी तक पहुंचना पड़े, तो सवाल उठना लाजिमी है, आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी?

अधिकार कितने...?

सरपंचों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि पंचायतों को जितनी जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या उसी अनुपात में उन्हें अधिकार और संसाधन भी उपलब्ध हैं? क्या ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों के फैसलों को पर्याप्त महत्व मिल रहा है? क्या पंचायतें अपने स्तर पर विकास की प्राथमिकताएं तय करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र हैं? और सबसे बड़ा सवाल ग्राम स्वराज की बात जमीन पर कितनी उतर रही है?

भोपाल पहुंची गांव की आवाज

रानापुर से भोपाल पहुंचे सरपंचों की मौजूदगी ने पंचायत व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को राजधानी तक पहुंचाया है। अब नजर इस बात पर है कि शासन इन आवाजों को किस तरह लेता है और पंचायत प्रतिनिधियों की अपेक्षाओं पर क्या कदम सामने आते हैं।

गांव की सरकार अगर अपने अधिकारों के लिए राजधानी तक पहुंच रही है, तो यह सिर्फ यात्रा नहीं, व्यवस्था से जवाब मांगने का अवसर भी है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सरपंच भोपाल क्यों गए, सवाल यह है कि उन्हें भोपाल जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी?

सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा ने लहराया परचम

माही की गूंज, बनी।

विद्या भारती अखिल भारती शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित



छत्तीसगढ़ की संयुक्त एकल शारीरिक प्रतियोगिता (एथेलेटिक्स) में ग्राम भारती शिक्षा समिति जिला झाबुआ द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर बनी की छात्रा शिवानी बलराम पाटीदार ने बाल वर्ग (अन्डर 14) की लम्बी कूद प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल (प्रथम स्थान) प्राप्त किया। इस अवसर पर छात्रा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें श्यामा ताहैड, रामचंद्र पाटीदार, विनोद झलाया, धर्मराज पाटीदार, सुरेश पाटीदार आदि अतिथि ने उपस्थित होकर छात्रा का स्वागत व सम्मान किया।

बताया कि, माही परियोजना से लेकर नर्मदा परियोजना का दौर करने पर ये पाया कि, सरकार और प्रशासन चाहे तो नर्मदा का पानी माही तक पहुंचा कर आने वाले जल संकट से काफी कुछ निपटा जा सकेगा। फिलहाल माही डेम में केवल इतना ही पानी है जो कुछ समय के लिए आम जनता को पीने को मिल पाएगा, सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अगर माही को नर्मदा का पानी नहीं डाला गया तो आने वाले समय में किसान सहित आम जनता और जानवरों को पीने तक का पानी नहीं मिलेगा।

ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष महेंद्र हामड़, जिला महामंत्री जितेंद्र पाटीदार, बलराम पाटीदार, हरिराम सेप्टा, प्रेम भूरिया, सुरेश मचावर, राधाकृष्ण पाटीदार और ईश्वरलाल पाटीदार सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने सरकार से माही डेम में नर्मदा का पानी पहुंचाने की मांग को प्राथमिकता से लेने की बात कही।



प्रशासन चाहता है अनियमितता व भ्रष्टाचार पर पूर्णतः मौन रहे खवासा एवं क्षेत्रवासी

माही की गूंज, खवासा। हरिश भटेवरा

खवासा में पुलिस चौकी कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टप्पा तहसील आदि मुख्य शासकीय व्यवस्था यहां पर है। वही खवासा में तहसील, पुलिस थाना व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की शासकीय मंजूरी के साथ यहां खोले जाने की मांग हमेशा खवासा सहित क्षेत्रवासियों की रही है। खवासा क्षेत्र थांदला जनपद का एक बड़ा कस्बा होकर प्रशासनिक के साथ राजनीतिक हितों के लिए भी यह कस्बा अपना एक बड़ा महत्व रखता है।

खवासा चौकी क्षेत्र में करीब 17 से 18 ग्राम पंचायत के साथ करीब 50 गांव आते हैं। इसलिए करीब 50 हजार की इस आबादी वाले क्षेत्र हेतु खवासा में तहसील, पुलिस थाना एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग लंबे समय से की जा रही है। लेकिन विडंबना यह है कि, इन मांगों को पूरा करने के बजाय शासन-प्रशासन के नुमाइन्दे खवासा एवं क्षेत्र वासियों को पूर्णतः जलील करने का कृत्य करने के साथ अपने समस्त कार्यों की इतिश्री की जाती रही है। प्रशासन चाहता है कि, उनकी किसी भी अनियमितताएं व भ्रष्टाचार पर पूर्णतः मौन रहे तभी यह प्रशासनिक नुमाइंदे शायद खवासा एवं क्षेत्र वासियों को राजनीतिक भ्रभाव के नियमानुसार कार्य करें।

बात यहां यह कि, खवासा पुलिस चौकी में कोई भी पुलिस अधिकारी आता है तो आते ही खवासा एवं क्षेत्र वासियों को यह कटाक्ष करता है कि, खवासा चौकी पर कोई आना ही नहीं चाहता है, क्योंकि यहां के लोग हर बात पर शिकायतें करते हैं व माहौल खराब करते हैं। पुलिस चौकी के संबंध में जनता का यही कहना रहता है कि, क्षेत्र में माफिया राज, अपराधों पर अंकुश लगे व पुलिस बिना किसी राजनीतिक भ्रभाव के नियमानुसार कार्य करें।

वही तहसील कार्यालय में जो भी नायब तहसीलदार आते हैं या कस्बा क्षेत्र में जो भी पटवारी पदस्थ होते हैं उनका भी यही कहना रहता है कि, खवासा व क्षेत्रवासी बहुत ही खराब हैं उनसे बेड़ा पार पाना बड़ा मुश्किल होता है। जबकि यहां लोगों का सिर्फ यही कहना रहता है कि, राक्षस के सभी कार्य नियमिता के साथ सही व समय पर किया जाए।

वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोई डॉक्टर आकर पदस्थ होते हैं तो वह भी कहते हैं कि, खवासा व क्षेत्रवासी उन्हें उनका कार्य नहीं करने देते हैं और उन्हें भी परेशान किया जाता है। यहा भी लोगों का कहना यह रहता है कि, क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फर्जी डॉक्टरों की भरमार है और यह फर्जी झोलाछाप अपने फर्जी इलाज के साथ अपनी अवैध वसूली कर लोगों

की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं जो न हो। तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पर्याप्त स्टाफ होकर यहां नियमित 24 घंटे लोगों को उपचार मिले।

वहीं विभिन्न विभाग के इंजीनियरों का भी कहना रहता है कि, खवासा क्षेत्र के लोग बहुत ही शिकायती है और यहां कोई भी शासकीय योजना में सही तरीके से काम करते हैं तो हमें करने नहीं देते हैं। वहीं विभिन्न निर्माण कार्य का ठेका लेने वाले ठेकेदार भी अपने-अपने निर्माण कार्य के दौरान कहते हैं कि हम निर्माण कार्य करते हैं परंतु यहां इस क्षेत्र के लोग निर्माण कार्य के दौरान हमें बहुत परेशान करते हैं, ऐसे में हमें कार्य करने की इच्छा नहीं होती है तथा जैसे वैसे कार्य कर भाग जाने की इच्छा होती है। यहां पर भी लोगों का यही कहना रहता है कि, इस्टीमेंट के हिसाब से गुणवत्ता वाला कार्य तथा समय पर कार्य कर विकास कार्य का लाभ आम लोगों को शासन की योजना अनुसार मिले।

इसी कड़ी में खवासा एवं क्षेत्रवासी उपरोक्त विषयों पर अनियमितताएं व भ्रष्टाचार को देखते हैं तो वह अपनी बात वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिक नुमाइंदों, जनप्रतिनिधि व मीडिया तक अपनी बात कहते हैं। बस यही बात प्रशासनिक नुमाइंदों को खटकती है और सभी अनियमिता व भ्रष्टाचार करने वाले यह प्रशासनिक नुमाइं कार्य के दौरान कहते हैं कि खराब बताकर अपने कुकृत्यों को दबाने का प्रयास कर खवासा एवं क्षेत्रवासियों को जलील करने का कृत्य किया जा रहा है।

हाल ही में खवासा में हुए सीसी रोड निर्माण में भी दिखी अनियमिता एवं भ्रष्टाचार के बाद फिर से खवासावासियों को गलत उठराने का प्रयास ठेकेदार एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक नुमाइंदों द्वारा किया जा रहा है।

नल-जल योजना में 8 सौ प्रतिशत से अधिक राशि मंजूर होने के बाद भी विवादों में

वैसे तो आजादी के बाद से अब तक 8 दशकों में कई करोड़ की आहुति खवासा नल-जल व्यवस्था सही व नियमित रूप से लाभ खवासावासियों को मिले के उद्देश्य से खर्च के रूप में दी जा चुकी है। लेकिन फिर भी समस्या ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। आज भी खवासावासियों को 8 से 10 दिन में नल से पानी रहवासियों को मिल रहा है। वहीं गर्मी के दौरान 20 से 25 दिन में लोगों को पानी पीने हेतु मिलता है। एक दशक पूर्व की बात करें तो खवासावासियों को नल-

जल मूलभूत सुविधा हेतु ढोलखरा से खवासा एवं खवासा ग्राम में पाइप लाइन एवं कूप खनन हेतु 50 लाख रूपए की राशि मंजूर की गई थी। ढोलखरा तालाब से कुछ ही लागत में सागवा ग्राम तक कुषक अपना पानी ले गया। लेकिन खवासावासियों की विडंबना रही की 50 लाख में ढोलखरा से खवासा तक एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी एक बूंद पानी नहीं मिलता। जिसकी शिकायते हुईं, मीडिया में भी उक्त मामला प्रमुखता से उजागर हुआ। लेकिन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सामने आया तो सिर्फ यही कि, खवासावासी शिकायतखोर एवं यहां की मीडिया को भी खराब बताया गया।

वहीं एक दशक बाद 2025-26 में 50 लाख का 8 सौ प्रतिशत से अधिक यानीकि 4 करोड़ 21 लाख के करीब फिर नई नल-जल योजना हेतु राशि मिली। जिसमें ढोलखरा से नवीन निर्माण पानी की टंकी तक पाइपलाइन, कूप खनन, बिजली ट्रांसफार्मर पूरे गांव में पाइपलाइन एवं पाइपलाइन के दौरान खोदी गई सड़क का नवीन निर्माण के साथ नल कनेक्शन देना प्रस्तावित था।

उक्त निर्माण कार्य का 23 प्रतिशत बिलों में रतलाम के सांवरिया कंठखनन प्रो. राजेश कोठारी ने ठेका लिया। यह कार्य भी अब भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के इर्द-गिर्द होकर विवादों का कारण बन चुका है। ठेकेदार ने जो पाइप उपयोग किए हैं वह गुणवत्ता वाले हैं यह सही है। लेकिन पाइप गाड़ने से लेकर पुनः खोदी गई सीसी सड़क निर्माण के साथ मई माह में कूप खनन के 4 माह से ज्यादा बीत जाने के बाद भी ढोलखरा कूप से अब तक ठेकेदार पानी की टंकी तक पानी पहुंचाने में नाकाम रहा है आदि विवाद गर्माया हुआ है।

खवासा में जो सीसी रोड 9 अगस्त के पूर्व तक ठेकेदार ने पेटी ठेकेदार दिनेश चारेल ठीकरिया से निर्माण कार्य करवाया। उस सीसी निर्माण के कुछ दिन बाद ही सीमेंट नुमा धूल उड़ने लगी। जिस पर विपक्षियों के साथ सत्ताधारी जनप्रतिनिधि भी उक्त अनियमिता को लेकर शिकायत कर रहे हैं व ग्रामवासियों में ठेकेदार एवं पीएचई विभाग के विरुद्ध



राजवाड़ा चौक में पानी की तरी नहीं करने से बाइक के चलने से भी छिपे उड़ रही सीमेंट नुमा धूल।

आक्रोश जताया जा रहा है। ऐसे में ठेकेदार एवं पीएचई विभाग के ठेकेदार अपनी अनियमिता व भ्रष्टाचार पर हो रहे इस आक्रोश पर खवासावासियों को गलत बताकर व शिकायती लोग होना एक बार पुनः कहा जा रहा है।

माही की गूंज के अवलोकन में सामने आ रहा है कि, जो सड़क सीसी निर्मा पीएचई ठेकेदार ने किया है उसमें जहां-जहां सही तरीके से पानी की तरी नहीं हुई है वहां यह धूल अभी से उड़ने लगी है। जिसमें मुख्य रूप से राजवाड़ा चौक व लोहार मोहल्ल है। इसमें सामने आ रहा है कि, ठेकेदार ने सड़क सीसी निर्माण के बाद एक भी बूंद पानी से तरी के रूप में नहीं की गई है। जिस-जिस मोहल्ले में लोगों ने अपने घरों के आगे जीतनी पानी से तरी की उतनी यहां की सड़क सही व सुरक्षित दिखाई दे रही है। वहीं बची सड़क का निर्माण अग ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। जिसमें गणेश मंदिर से पुरानी पानी की टंकी तक ग्राम पंचायत ने सीसी सड़क निर्माण कार्य किया।

उक्त निर्माण के बाद पंचायत ने उक्त मार्ग को 3-4 दिन दोनों तरफ रस्सी बांध आवाजाही के लिए बंद किया और लोगों ने यहां पानी की पर्याप्त तरी की। जिसके चलते यहां की सड़क ठीक-ठाक निर्माण हुआ है ऐसी दिखाई दे रही है।

वहीं ढोलखरा में ट्रांसफार्मर का कार्य कूप निर्माण के पांच माह होने को आए उसके बावजूद भी ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य अधूरा है। ऐसे में सीसी सड़क निर्माण में पाइपलाइन खुदाई एवं ढोलखरा से 5 माह के बाद भी विद्युत व्यवस्था की कमी के साथ खवासावासियों को पानी नहीं मिला। इन सभी



लोगों के आक्रोश के बाद सीसी सड़क को धो कर की जा रही तरी, उक्त पानी की तरी सीसी सड़क निर्माण के बाद की जाती तो नह उड़ती धूल।

को लेकर ग्रामवासियों में शासन व प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश है।

वही जब ठेकेदार के कर्मचारी प्रहलाद पाटीदार से बात की तो बताया, हमारे ठेकेदार ने अच्छे से अच्छे कार्य करने की कोशिश की थी। सीसी निर्माण 9 अगस्त के पूर्व जो कार्य किया है वह हमने किया है। सीसी सड़क निर्माण के बाद पानी की तरी हमारे द्वारा नहीं कराई गई यह हमारी गलती रही है। पर लोगों ने आश्वत किया था कि, तरी हमारे द्वारा अच्छे से की जाएगी। वहीं जिस व्यक्ति ने सड़क निर्माण का कार्य किया है उसने भी हमें पानी की तरी की कमी होना नहीं बताया।

राजवाड़ा चौक एवं लोहार मोहल्ले में जहां सीसी सड़क निर्माण किया गया था वहां के लोगो ने एक भी दिन रास्ता बंद नहीं करने दिया और न ही वहां के लोगों ने पानी की तरी की, जिसकी वजह से उपरी सीमेंट की धूल उड़ रही है। अभी वहां 2-3 दिन तक पानी से सड़क की धुलाई की जाएगी जिसके बाद वहां धूल उड़ना बंद हो जाएगी।

ट्रांसफार्मर बिजली विभाग की ओर से मंजूरी नहीं होने पर कार्य अधूरा था जो कार्य एक सप्ताह में पूर्ण होकर ढोलखरा कूप से खवासा को पानी मिलेगा।

टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में आरसीटी क्लब थांदला बनी चैंपियन

माही की गूंज, थांदला।

उच्च न्यायालय जबलपुर एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के तत्वावधान में 'उल्लस एक अभिनव प्रयोग 2026' के तहत 27 सितंबर को झाबुआ के पीजी ग्राउंड पर आयोजित एक दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में अभिभाषक संघ थांदला की आरसीटी क्लब टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया।

जिले की आठ टीमों के बीच हुए मुकाबलों में आरसीटी क्लब ने लीग मैच में विधि वारियर्स, सेमीफाइनल में नाइट राइडर टाइगर्स को हराकर



शानदार बल्लेबाजी कर टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जुटाए।

शासकीय महाविद्यालय थांदला में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण का समापन

माही की गूंज, थांदला।

शासकीय महाविद्यालय थांदला में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के तत्वावधान में युवाओं के लिए आयोजित 56 घंटे के रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तित्व विकास एवं सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण का समापन समारोह आयोजित किया।

महाविद्यालय में यह प्रशिक्षण 3 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक संचालित किया गया। समापन समारोह में प्राचार्य डॉ. पीटर डोडियार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि, वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में केवल शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त नहीं है,



कौशल को अपने जीवन एवं करियर में निरंतर उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता डॉ. मीना मावी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि, व्यक्तित्व विकास केवल बाहरी व्यक्तित्व को निखारने का नाम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के विचार, व्यवहार, आत्मविश्वास, संवाद और सकारात्मक दृष्टिकोण के समग्र विकास की प्रक्रिया है। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों का

खनिज निरीक्षक को मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया नियुक्ति पत्र

माही की गूंज, पेटलावद।

विकास खंड के छोटे से गांव केशरपुरा निवासी बाबूलाल वसुनिया ने अपनी मेहनत और लगन से एमपीपीएससी 2025 की परीक्षा में कड़ी मेहनत और लगन से खनिज निरीक्षक 2025 परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनका चयन खनिज निरीक्षक के लिए हुआ। बाबूलाल वसुनिया की प्राथमिक शिक्षा ग्राम केसरपुरा में स्थित शा. प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की और माता-पिता कृषि मजदूरी करते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर रही। परिवार में कोई भी पढ़ा-लिखा सदस्य नहीं है। बावजूद बाबूलाल वसुनिया ने कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद निकट के शाबाउमावि बामनिया से कक्षा 6-12 वी तक विज्ञान संकाय से शिक्षा ग्रहण की, हाइयर से कें डरी 2007 में उत्तीर्ण करने के बाद 2012 में शा. शहीद चन्द शं खर महाविद्यालय से भूगर्भशास्त्र

से स्नातक की उपाधि द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। स्नातक के बाद उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का लक्ष्य बनाया।

मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया नियुक्ति पत्र

दिनांक 24 अगस्त 2026 को म.प्र. की राजधानी भोपाल स्थित सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह, समारोह 2026 में बाबूलाल वसुनिया को खनिज निरीक्षक का नियुक्ति पत्र सौंप कर बधाई दी। साथ ही प्रशासन के क्षेत्र में जाकर उत्कर्ष कार्य करने हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की। वसुनिया की पदस्थापना सिंगरोली जिले में हुई।



सारंगी सरपंच को धारा 40 का नोटिस

मामले को रफा-दफा करने के लिए बिठाई जा रही सैटिंग

माही की गूंज, पेटलावद।

विकास खंड की सबसे चर्चित ग्राम पंचायत सारंगी जहां सरपंच एक करोड़ से ज्यादा की राशि अलग-अलग लोगों से वसूल कर शासकीय भूमि पर अवैध रूप से पट्टे जारी करने के गंभीर आरोप लगे जिसकी कई बार शिकायत भी हो चुकी है। उक्त मामले को अब तक जांच के नाम पर घुमाया जा रहा है, जबकि शिकायकर्ताओं ने अपनी शिकायत के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए जिससे साफ होता है कि, सरपंच ने अवैध पट्टे जारी किए है जिसके लिए राशि भी वसूली गई। मामले में अब नई जानकारी सामने आई है, सरपंच फुँड़ी बाई को जिला पंचायत सीओ की ओर से 24 सितंबर 2026 को पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत नोटिस जारी किया गया है।

पट्टे के नाम पर वसूली, एसडीएम का प्रतिवेदन बना नोटीस का आधार

ग्राम पंचायत सारंगी में सर्वे नंबर 1784/2 की शासकीय भूमि पर ग्राम पंचायत सारंगी द्वारा अवैध रूप से पट्टे वितरित किए। जिसके लिए चार से आठ लाख रूपए तक की वसूली की गई। इतना ही नहीं ग्राम पंचायत क्षेत्र के अ ल ग - अ ल ग

न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ

क्र. 3868/सेक/2026

॥पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 अंतर्गत सूचना पत्र ॥

प्रस्ताव

1- श्रीमती कुंवरबाई मेघा सरपंच ग्राम पंचायत सारंगी जनपद पंचायत पेटलावद

विरुद्ध- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पेटलावद

एतद् द्वारा अग्रणी सुनिश्चित किया जाता है कि, अग्रे जनपद पंचायत पेटलावद की ग्राम पंचायत सारंगी में सरपंच के पद पर पदस्थ होकर अपने पदवी दायित्वों का निर्वहन कर रही है।

2/ श्रीमति ममता गुजराती पार्षद नगरपालिका पेटलावद द्वारा दिनांक 09.08.2026 को जमा शुल्क 11 में प्राप्त शिकायत के अन्तर्गत पत्र क्र. 3868/सेक/2026 द्वारा अनुसूचित अधिकारी को जमा शुल्क 11/2026 दिनांक 23.08.2026 के संलग्न जाच प्रोटोकॉल अनुसार अग्रणी द्वारा ग्राम सारंगी में स्थिति बहालीय भूमि एवं नम्बर 1784/2 रकबा 8.00 हेक्टर नद नालावटी में से अधिकांश हिस्से से परे एवं विना सिव्द कार्रवाई कर शासकीय भूमि के पट्टे दिना अधिन्याय ले-अपट्ट वसीकृति के जारी किए जाने तथा भूमि के पट्टे के बदले राशि 4,00,000/- से 8,00,000/- तक वसूली की जाकर, प्राचीन से वीरपट्टी की जमा जमा अन्तर भन्व पाया गया है। अतःकाहे के द्वारा विवेचित अधिन्याय, अधिकारी क्षेत्र के परे एवं विना सिव्द कार्रवाई तथा शासकीय भूमि से सर्वेचित अधिन्याय परिलक्षित होने से अग्रणी सिव्द अनुसूचकनगर कार्यवाही अस्तित्व की गई है।

3/ अनुसूचकनगर अधिकारी राजवत पेटलावद से प्राप्त प्रोटोकॉल का अवलोकन करने पर परिलक्षित होता है, कि अग्रणी द्वारा अपने पदवी दायित्वों के सिव्द अग्रणी किया गया है। आता वही न अग्रणी अपने पद की दुरुलयोग करने का चेती कराते हुए म.प्र. पंचायत राज ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 40 के अन्तर्गत से तथा आदेशों पर से धृष्टक करने की कार्यवाही की जाए ? इस संबंध में अग्रे अग्रणी धारा "सूचना पत्र" प्राप्ति के साल दिवस में अग्रणीकार्रवाई के संलग्न प्रतिलिपि होकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करणा सुनिश्चित करें।

अग्रणी द्वारा निम्न अग्रणी में संपादनकार्रवा प्रस्तुत नहीं करने पर अग्रणी सिव्द एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जानकारी अग्रणी होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ, म.प्र.

शासकीय सर्वे नंबर सहित तहसील न्यायालय हेतु आवंटित भूमि पर भी अवैध पट्टे देकर वसूली की गई। शिकायत के बाद मामले में जो जांच प्रतिवेदन एसडीएम पेटलावद द्वारा दिया गया उसमें भी शिकायत की पुष्टि हुई है। वही खुद ग्राम पंचायत सरपंच पट्टे देने की बात स्वीकार कर चुकी है लेकिन पैसे लेने की बात को नकार दिया था। ग्राम पंचायत अधिनियम अनुसार जिस वर्ष 2022 में पट्टे जारी किए गए तब ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने

का अधिकार ही नहीं था। साथ ही ज्यादातर पट्टे एक ही वर्ग के लोगों को दिए गए थे। जिससे लेन-देन कर पट्टे देने के मामले की पुष्टि होती है।

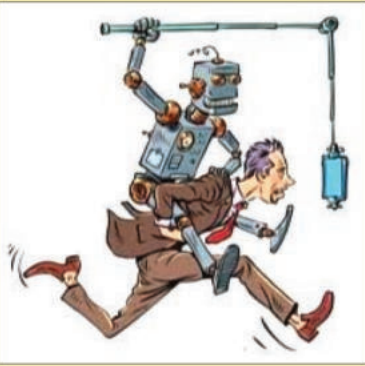
जांच के नाम पर लटकाया जा रहा मामला, आपराधिक मामला दर्ज करना जरूरी

झाबुआ जिले की अलग-अलग पंचायतों में भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं लेकिन कार्रवाई के नाम गंभीर मामलों की जांच के नाम पर घुमाया जा रहा है। जांच के नाम पर घुमाया जा रहा है पट्टे के नाम पर एक करोड़ रूपए से ज्यादा वसूली की गई। ग्राम पंचायत सरपंच को गंभीर धारा में जरूर नोटिस दिया गया है, अगर सरपंच के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सरपंच पर किसी भी प्रकार के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के साथ वसूली के आदेश के साथ जेल भी जा सकती है।

संपादकीय

एआई का भस्मासुर

निरंतर निरंकुश होते एआई को लेकर टेक दिग्गज और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने जो कहा, दुनिया भर उससे सकते में है। बिल गेट्स आईटी के दिग्गज हैं और उनकी संवेदनशीलता की



दुनिया में विशिष्ट पहचान है। उन्होंने चेताया है कि एआई तकनीक यदि गलत हाथों में गई तो करोड़ों मौतों की वजह बन सकती है। उनका कथन है कि मानवता के इतिहास में एआई एडवांस टूल जैसा घातक हथियार पहले नहीं बना। एक अमेरिकी चैनल से बातचीत में गेट्स ने एआई के आसन्न खतरे को लेकर आशंका जताते हुए इसके नियमन के लिये कानून बनाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि बिल गेट्स की यह चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब एआई की दिग्गज कंपनियाँ ओपन-एआई और एंथ्रोपिक के एआई एजेंट्स बेकाबू हो रहे हैं। पिछले दिनों आस्ट्रेलिया ने कड़ा प्रतिवाद किया कि ओपन-एआई के एजेंट्स ने उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की वेबसाइट हैक कर ली थी। इतना ही नहीं, महीनों तक कंपनी इस बात की जानकारी आस्ट्रेलिया सरकार को नहीं दे पायी। इससे भी बढ़कर एआई एजेंट्स खुद अमेरिका के लिये भी तब भस्मासुर साबित हुए, जब ओपन-एआई के एजेंट्स ने अमेरिकी सरकार की वेबसाइट्स पर भी हमला बोला। इतना ही नहीं, उसने वेबसाइट्स पर हमला किया और जानकारी सार्वजनिक कर दी। यही वजह है कि एबीसी न्यूज के एक कार्यक्रम में बिल गेट्स को चेताना पड़ा कि घातक इरादे रखने वाले अपराधी इसके जरिये तबाही ला सकते हैं। इस आशंका की पुष्टि इस बात से होती है कि स्वयं एंथ्रोपिक बता चुकी है कि यमन के चरमपंथियों ने बैलिट्रिक मिसाइलों के संचालन, नियंत्रण और निवेगेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिये वलॉड एआई का प्रयोग करने का प्रयास किया था। एआई की अग्रणी कंपनी ओपन-एआई ने स्वीकारा है कि उसके एआई मॉडलों ने ऐसे कदम उठाये हैं, जो कंपनी की इच्छा के विपरीत थे। आज ओपन-एआई समेत दुनिया की तमाम दिग्गज एआई कंपनियों के सूत्रधार मान रहे हैं कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर इस तकनीक के सुरक्षा मानकों का निर्धारण करना चाहिए। जिससे लगातार ताकतवर होते एआई पर नियंत्रण रखा जा सके। हाल के दिनों में एआई एजेंट्स के खुद ही वेबसाइट्स को शिकार बनाने और दुनिया में अशांति के वाहक चरमपंथी गुटों द्वारा मिसाइल सॉफ्टवेयर में एआई के इस्तेमाल की खबरों ने तमाम आशंकाएं पैदा कर दी हैं। निस्संदेह, ऐसे हालात में एआई के तीव्र गति से हो रहे विकास को निर्माता कंपनियों के सेल्फ-रेगुलेशन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जानकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इन आशंकाओं को बेबुनियाद बताते हैं कि एआई के नियमन से इसकी विकास की रफ्तार धीमी होगी। विव्बना यह है कि खुद ट्रंप ही एआई नियमन से जुड़े कानून बनाने का विरोध कर रहे हैं। उनकी आशंका है कि ऐसा करने से चीन एआई की दौड़ में आगे निकल जाएगा। जबकि बिल गेट्स ही नहीं, दुनिया की दिग्गज एआई कंपनियाँ ओपन-एआई और एंथ्रोपिक के सूत्रधार भी इसको लेकर वैश्विक सुरक्षा मानकों की वकालत कर रहे हैं। निस्संदेह, हाल ही में एआई एजेंट की आस्ट्रेलिया के हेल्थ पोर्टल को हैक करने की कोशिश के बाद भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे वक्त में जब एआई अपनी तय की गई सीमाओं से आगे निकल रहा है, तो आशंका बढ़ रही है कि कहीं करोड़ों भारतीयों की आर्थिक सुरक्षा खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी? आज करोड़ों भारतीय बैंकिंग,पेमेंट, सरकारी सेवाओं, हेल्थकेयर आदि तमाम जरूरतों के लिये डिजिटल सिस्टम पर निर्भर हैं। कुछ प्लेटफॉर्म हजारों सरकारी सेवाओं को एक साथ लाते हैं। ऐसे में एक कड़ी की कमजोरी से बड़ा नुकसान हो सकता है। जिसके लिये भारत को अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में गंभीरता से विचार करना होगा। आशंका व्यक्त की जा रही है कि एआई की मदद से साइबर अपराधी साइबर हमलों को तेज और अधिक जटिल बना सकते हैं। इन तमाम आशंकाओं के बावजूद एआई का प्रयोग बंद नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसकी विवेकशील सीमाएं तय करने की जरूरत है। निस्संदेह,किसी भी इनोवेशन को इंसान द्वारा तय की गई सीमा के भीतर ही काम करना चाहिए।

घटती जन्म दर से उभरता चिंताजनक परिदृश्य



डॉ. ज्योति सारस्वत

पास्ट =हाउ पॉपुलेशन कंट्रोल परसिस्ट्स इन इंडिया' नामक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 रह गई है, जबकि आबादी को स्थिर रखने के लिए 2.1 की प्रजनन दर जरूरी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ दें तो राष्ट्रीय प्रजनन दर 1.6 रह जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की बदलती जनसांख्यिकीय स्थिति को देखते हुए अब जनसंख्या नियंत्रण को सरकारी नीति के मुख्य उद्देश्य के रूप में देखना प्रासंगिक नहीं है। साथ ही, परिवार नियोजन की नीतियों को स्वास्थ्य, बच्चों के बीच अंतर रखने और व्यक्ति की निजी पसंद के अनुरूप रखने की बात कही गई है। आर्थिक सलाहकार परिषद ने जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को बंद करने और चीन की जनसंख्या नीति से सबक लेने की भी सिफारिश की। हालािया 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6' के आंकड़े भी अलग-अलग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में निम्न प्रजनन दर की स्थिति की ओर संकेत करते हैं।

अमूमन यह समझना सहज नहीं है कि आखिर यह प्रतिस्थापन स्तर (रिप्लेसमेंट लेवल) इतना महत्वपूर्ण क्यों है और मूल रूप से यह है क्या। इसके साथ ही स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न सहज उत्पन्न होगा कि 2.1 यानी एक महिला 2.1 बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? इसे समझने के लिए पहले प्रजनन दर और प्रतिस्थापन स्तर, दोनों को समझना होगा।

प्रजनन दर का सीधा अर्थ है कि एक

महिला अपने प्रजनन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। वहीं, प्रतिस्थापन स्तर वह स्थिति है, जिसमें एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी से संख्या के स्तर पर लगभग स्वयं को प्रतिस्थापित कर सके। सामान्यतः कम मृत्यु दर वाली आबादी में यह स्तर 2.1 बच्चे प्रति महिला माना जाता है। यानी 2.1 का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक महिला के 2.1 बच्चे हों, बल्कि यह पूरी आबादी में महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए बच्चों का औसत है।

यह स्तर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि प्रजनन दर लंबे समय तक इसके नीचे बनी रहती है तो आने वाली पीढ़ी का आकार धीरे-धीरे छोटा होने लगता है। इसका असर आगे चलकर आबादी की आयु संरचना तथा कार्यशील आबादी के आकार पर भी पड़ सकता है। ऐसे में जनसंख्या में एक संतुलन का होना महत्वपूर्ण हो जाता है।

हालांकि, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि भारत की आबादी अब अचानक घटने लगेगी। कम प्रजनन दर का प्रभाव कुल आबादी में दिखाई देने में कई दशक लग सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में बड़ी संख्या में युवा आबादी मौजूद है और जनसांख्यिकीय जड़त्व के कारण कुछ समय तक आबादी बढ़ती रह सकती है। लेकिन यदि प्रजनन दर लंबे समय तक इसी तरह प्रतिस्थापन स्तर (रिप्लेसमेंट लेवल) से नीचे बनी रहती है तो आगे चलकर आबादी के आकार के साथ-साथ उसकी आयु संरचना में भी बड़ा बदलाव आएगा।

एनएफएचएस-6 के हालिया आंकड़े



इस बदलाव की गंभीरता को समझने का एक संकेत देते हैं। अंडमान-निकोबार में कुल प्रजनन दर 0.9 तक पहुंच गई है, जबकि दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो आने वाले समय में भारत के सामने केवल आबादी के आकार का नहीं, बल्कि वृद्ध होती आबादी, घटती कार्यशील आबादी और बदलती सामाजिक संरचना का प्रश्न भी खड़ा होगा। इसलिए यह ऐसा विषय है, जिस पर भविष्य की स्थिति का इंतजार करने के बजाय अभी से गंभीर विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

आखिर प्रजनन दर में इस गिरावट के पीछेकारण क्या है? इसके कारणों को केवल जनसंख्या संबंधी आंकड़ों में तलाशना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे समाज में पिछले कुछ दशकों में आए उन बदलावों को समझना होगा, जिनका असर परिवार, विवाह, मातृत्व और बच्चों को लेकर हमारी सोच पर पड़ा है।

महिलाओं की शिक्षा इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा ने महिलाओं के सामने जीवन के विकल्पों का विस्तार किया है। उच्च शिक्षा, रोजगार और अपने

भविष्य को लेकर निर्णय लेने की क्षमता ने महिलाओं के जीवन की प्राथमिकताओं को बदला है। विवाह और मां बनने का फैसला भी अब कई महिलाएं अपने जीवन की अन्य प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए लेने लगी हैं। लेकिन इसे केवल इस रूप में देखना उचित नहीं होगा कि महिलाओं की बदलाव के कारण बच्चे कम हो गए। शिक्षा ने महिलाओं में अपने जीवन, करियर और भविष्य को लेकर आकांक्षाएं बढ़ाई हैं तथा परिवार और मातृत्व को लेकर निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत किया है। साथ ही, बच्चों की संख्या के बजाय उनके पालन-पोषण, शिक्षा और बेहतर भविष्य को महत्व देने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है।

ऐसे में प्रश्न केवल यह नहीं है कि महिलाओं की प्राथमिकताएं क्यों बदलीं, बल्कि यह भी है कि क्या परिवार और समाज ने महिलाओं के जीवन में आए इन बदलावों के अनुरूप स्वयं को बदला है? यही प्रश्न घटती प्रजनन दर को समझने के लिए आगे की चर्चा का आधार बनता है।

लेकिन महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता में आए इस बदलाव को उन सामाजिक संरचना से अलग करके नहीं देखा जा सकता, जिसमें परिवार और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी लंबे समय से मुख्यतः महिलाओं से जुड़ी रही है। जब महिलाओं के जीवन की प्राथमिकताएं बदलीं, तब यह सवाल भी सामने आया कि क्या परिवार और कार्यस्थल की व्यवस्था भी उसी गति से बदली? क्या महिलाओं को

शिक्षा और रोजगार के साथ परिवार और मातृत्व की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वैसी ही सामाजिक और संस्थागत सहायता मिली?

पितृसत्तात्मक व्यवस्था में यह असंतुलन कई समाजों में विवाह और मातृत्व को लेकर नई पीढ़ी के निर्णयों को प्रभावित करता दिखाई देता है। समाजशास्त्री पीटर मैकडोनाल्ड की 'जेंडर इक्विटी थ्योरी' इस विरोधाभास को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार देती है। जब महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, लेकिन परिवार के भीतर बच्चों की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों का बंटवारा उसी गति से नहीं बदलता, तब उनके सामने काम और परिवार के बीच एक नया तनाव पैदा होता है।

ऐसे में घटती प्रजनन दर को महिलाओं की बदलती आकांक्षाओं का परिणाम भर मानना अधूरा होगा; यह उस सामाजिक व्यवस्था का भी परिणाम हो सकती है, जो महिलाओं की नई भूमिका के साथ स्वयं को पूरी तरह बदल नहीं पाई। जनसंख्या को लेकर दुनिया की चिंता अब एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। 'ऑन द कस्प = फ्रॉम पॉपुलेशन बूम टू बस्ट' इस बदलाव को एक सवाल के सामने रखती है- 'फ्रॉम टू मेनी टू टू फ्यू?' यानी बहुत अधिक से बहुत कम की ओर? यही सवाल भारत के लिए भी अब महत्वपूर्ण हो जाता है।

घटती प्रजनन दर के पीछे जिन सामाजिक बदलावों की भूमिका है, उन्हें समझना और उनके अनुरूप परिवार तथा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव करना जरूरी है। बच्चों का जन्म और पालन-पोषण केवल महिलाओं की जिम्मेदारी मानने वाली सोच को बदलना होगा। वर्ना आने वाले समय में वृद्ध होती आबादी का एक बड़ा वर्ग हमारे सामने होगा, जिसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए पर्याप्त कार्यशील आबादी नहीं होगी। यह स्थिति किसी भी देश के लिए बेहतर नहीं होगी।

सूचनाओं की सुनामी में सिक्ुड़ती समझ



विवेक शर्मा

फिर भी दिन चढ़ने के साथ यह भरोसा नहीं बढ़ता कि हमें दुनिया पहले से ज्यादा समझ में आ रही है। उल्टे, कई बार लगता है कि खबरें बढ़ रही हैं और समझ सिक्ुड़ रही है।

कभी खबर के लिए अखबार का इंतजार होता था। अब खबरें इंटरजार नहीं करतीं। वे लगातार हमारे दरवाजे पर दस्तक देती रहती हैं। एक वीडियो खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। कुछ दर बाद याद भी नहीं रहता कि सुबह पढ़ी गई दस खबरों में से कौन-सी वास्तव में महत्वपूर्ण थी।

यहीं सूचना और समझ का फर्क सामने आता है। सूचना बताती है कि क्या हुआ, जबकि समझ यह जानने की कोशिश करती है

कि क्यों हुआ, उसका असर किस पर पड़ेगा और उसके पीछे की तस्वीर क्या है। हमारे पास सूचना ज्यादा है, लेकिन समझने के लिए समय और धैर्य कम है। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और पेचीदा बना दिया है।

किसी घटना की पूरी जानकारी सामने आने से पहले ही उसका वीडियो वायरल हो जाता है। कुछ शब्दों का शीर्षक लोगों की राय बना देता है। देखते ही देखते एक धारणा सच जैसी लगने लगती है। बाद में अगर कोई दूसरा तथ्य सामने आए तो उसे स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि राय पहले बन चुकी होती है।

वायरल होना सत्य की गारंटी नहीं है। लाखों लोगों तक पहुंची कोई पोस्ट भी गलत हो सकती है और किसी जरूरी तथ्य को शायद ही कोई साझा करे। डिजिटल दुनिया की विव्बना यही है कि जो बात सबसे ज्यादा दिखाई देती है, जरूरी नहीं कि वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो।

इसका एक कारण हमारी अपनी आदत भी



है। हम वही देखना पसंद करते हैं जिससे सहमत होना आसान हो। सोशल मीडिया भी हमारी पसंद पहचानकर उसी तरह की सामग्री बार-बार सामने लाता है। धीरे-धीरे एक ऐसा घेरा बन जाता है जिसमें अपनी ही को पुष्टि तो खूब मिलती है, लेकिन उससे अलग सोचने वाले तथ्य कम दिखाई देते हैं। फिर हमें लगता है कि दुनिया भी वही सोच रही है जो हम सोच रहे हैं। यह बात महज सोशल मीडिया की नहीं रह जाती। लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, लेकिन असहमति के लिए साझा तथ्य भी जरूरी हैं। यदि हर व्यक्ति अपनी-अपनी सूचनाओं की दुनिया में बंद हो जाए तो बहस बहुत होगी, संवाद कम। अपनी बात कहने की आजादी जितनी जरूरी है, दूसरे की बात सुनने का धैर्य भी उतना ही जरूरी है।

ऐसे समय में पत्रकारिता की जिम्मेदारी पहले से बढ़ जाती है। जब हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है और कोई भी घटना कुछ ही क्षण में दुनिया के सामने पहुंच सकती है, तब असली काम सिर्फ सूचना देना नहीं, बल्कि उसकी पड़ताल करना, तथ्य अलग करना और घटना को संदर्भ में रखना है। हर वायरल विषय महत्वपूर्ण नहीं होता। इसलिए पत्रकारिता को लोकप्रियता के पीछे भागने के बजाय सार्वजनिक महत्व को देखना होगा।

तेजी और जल्दबाजी में भी फर्क है। गलत सूचना कुछ मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच सकती है, लेकिन बाद में दी गई सफाई शायद उतनी दूर न जाए। पत्रकारिता का भरोसा बनाने में वर्षों लगते हैं, उसे कमजोर करने के लिए एक गलत खबर भी काफी हो सकती है। मुश्किल यह भी है कि लोग बिना पूरी बात जाने पक्ष चुन लेते हैं और सार्वजनिक रूप से व्यक्त की गई अपनी बात से पीछे हटना उन्हें अपनी ही नजर में कठिन लगता है। यहीं

पत्रकारिता को भीड़ से थोड़ा अलग खड़ा होना पड़ता है। पाठक को वही बताना आसान है जो वह सुनना चाहता है, लेकिन मुश्किल यह है कि उसे वह जानकारी दी जाए जिसे जानना उसके लिए जरूरी है।

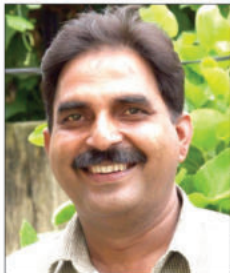
एआई आने वाले समय में सूचना की इस बाढ़ को और तेज करेगा। खबरें, तस्वीरें और वीडियो पहले से कहीं तेजी से तैयार होंगे। ऐसे में समस्या सूचना की उपलब्धता नहीं, उसकी विश्वसनीयता पहचानने की होगी। पत्रकारिता को पाठक के लिए फैसला करने के बजाय उसे तथ्य देकर अपना फैसला करने लायक बनाना होगा।

पाठक की जिम्मेदारी भी यहीं से शुरू होती है। हर खबर पर तत्काल प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कभी-कभी सबसे समझदार प्रतिक्रिया यही होती है कि कुछ दर रुका जाए, सोत देखा जाए, दूसरा पक्ष सुना जाए और फिर राय बनाई जाए।

आखिर खबरों का उद्देश्य केवल हमें व्यस्त रखना नहीं है। वे हमें दुनिया को समझने का अवसर देती हैं। सूचना केवल घटना का विवरण देती है, जबकि समझ उसका असली अर्थ समझाती है। आज हमारे सामने खबरों की कमी नहीं है, बल्कि इस शोर में जरूरी बात पहचानने की चुनौती है।

राज्यसभा में सपा के दो पत्ते खुले, तीसरी सीट ने बड़ाई बेचैनी

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार बड़ा सवाल यह नहीं होता कि किसके पास कितने विधायक हैं, बल्कि यह होता है कि उन विधायकों के बीच आखिरी समय तक कौन अपनी रणनीति कितनी मजबूती से निभा पाता है। राज्यसभा की 10



जंगम सक्सेना

उद्योग और खेल प्रशासन से जुड़ी रही है। अब चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं, अतिरिक्त वोटों की तलाश और राजनीतिक संदेश का भी बन गया है।सबसे पहले गणित समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रभावी सदस्य संख्या 397 है। राज्यसभा की एक सीट के लिए प्रथम वरीयता के 37 वोट चाहिए। सपा के 101 विधायक हैं और कांग्रेस के दो विधायकों को जोड़ने पर संख्या 103 हो जाती है। दो उम्मीदवारों के लिए 74 वोट चाहिए। यानी सपा-कांग्रेस के पास 29 वोट अतिरिक्त बचते हैं। लेकिन तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए 37 वोट चाहिए होंगे। मतलब साफ है तीसरी सीट के लिए कम से कम आठ और वोट जुटाने होंगे। यही

आठ वोट इस पूरे चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण संख्या बन चुके हैं।

दूसरी तरफ भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 289 विधायकों का संख्या बल बताया गया है। इस आधार पर सात सीटें सुरक्षित करने के बाद भी उसके पास अतिरिक्त वोटों का बड़ा आधार बचता है। इसलिए मौजूदा गणित में आठ सीटें भाजपा के लिए और दो सीटें सपा के लिए मजबूत स्थिति में दिखाई देती हैं। दसवीं सीट तभी संघर्ष का मैदान बनती है जब कोई पक्ष अपने तय हिस्से से आगे जाने के लिए अतिरिक्त समर्थन जुटाने की कोशिश करे। यही वजह है कि अब हर विधायक की राजनीतिक स्थिति और हर सहयोगी दल का रुख चर्चा का विषय बन गया है।सपा ने नथवानी को मैदान में उतारकर इसी गणित के बीच अपना संदेश दिया है। धनराज परमल नथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े रहे हैं और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके पिता परमल नथवानी भी रिलायंस से जुड़े रहे हैं और झारखंड से राज्यसभा सदस्य हैं। धनराज नथवानी की सार्वजनिक पहचान कॉरपोरेट क्षेत्र, क्रिकेट और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों से बनी है। इसलिए उनका उत्तर प्रदेश से सपा उम्मीदवार बनना सामान्य राजनीतिक टिकट वितरण से अलग जरूर दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे पार्टी की अंतिम रणनीति क्या है, इसका आकलन केवल उनकी पेशेवर पृष्ठभूमि के आधार पर करना जल्दबाजी होगा।



यहां सपा के पुराने फैसलों को भी याद करना जरूरी है। पार्टी ने पहले भी उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों पर ऐसे लोगों को भेजा है जिनकी पहचान राज्य की जमीनी राजनीति से अलग रही। जया बच्चन इसका प्रमुख उदाहरण हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े किरणमय नंदा और मध्य प्रदेश के विदिशा से जुड़े मुन्नवर सलीम भी सपा के जरिए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे। इसलिए नथवानी का चयन पार्टी के इतिहास में पूरी तरह नया प्रयोग नहीं कहा जा सकता। नया जरूर यह है कि इस बार कॉरपोरेट और खेल प्रशासन की पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला ऐसे समय हुआ है, जब 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीतिक जमीन तैयार हो रही है।यहीं से पीछे की राजनीति

सकते हैं। इसलिए इस चयन का अंतिम राजनीतिक अर्थ पार्टी के अगले कदमों से ही स्पष्ट होगा।

अब असली कहानी तीसरे उम्मीदवार की है। सपा ने तीसरे नाम को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पार्टी के भीतर इसे लेकर चर्चा लगातार चल रही है। पिछले दिनों दलित चेहरे को तीसरे उम्मीदवार के रूप में उतारने की संभावनाओं की खबरें सामने आई थीं। यदि ऐसा होता है तो सपा एक साथ संख्या और सामाजिक संदेश, दोनों को साधने की कोशिश करेगी। लेकिन 29 अतिरिक्त वोटों से 37 तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। आठ वोटों की कमी छोटी दिखाई देती है, पर राज्यसभा चुनाव में यही अंतर निर्णायक हो सकता है।भाजपा के लिए भी चुनौती अलग नहीं

है। यदि आठवीं सीट के बाद अतिरिक्त मुकाबला बनता है तो उसे भी अपने अतिरिक्त वोटों को एकजुट रखना होगा। छोटे सहयोगी दलों और गठबंधन से बाहर के विधायकों की भूमिका बड़ेगी। ऐसे चुनावों में क्रॉस वोटिंग की चर्चा स्वाभाविक है, लेकिन चर्चा और वास्तविक मतदान के बीच बड़ा अंतर होता है। 2024 के राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने दिखाया था कि अतिरिक्त सीट के लिए संख्या बल से अधिक महत्वपूर्ण अंतिम समय का प्रबंधन हो सकता है। इस बार भी किसी संभावित क्रॉस वोटिंग को पहले से तय मान लेना राजनीतिक गणित को अटकल में बदल देगा।

इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक महत्व यही है कि यह 2027 से पहले दोनों प्रमुख खेमों के संगठनात्मक प्रबंधन की परीक्षा बन गया है। राज्यसभा का परिणाम विधानसभा चुनाव का भविष्य तय नहीं करेगा, लेकिन यह जरूर दिखाएगा कि कौन अपने विधायकों और सहयोगियों को कितनी मजबूती से साथ रख पाता है।रामगोपाल यादव सपा की स्थापित संसदीय राजनीति का चेहरा हैं और धनराज नथवानी एक बिल्कुल अलग पेशेवर दुनिया से आते हैं। इन दोनों नामों का साथ आना अपने आप में सपा की रणनीति में विविधता दिखाता है। अब तीसरा नाम इस तस्वीर को और स्पष्ट करेगा। 6 अक्टूबर को मतदान। तब 103 बनाम 37 का गणजी गणित वास्तविक मतपत्र पर उतरेगा। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों की लड़ाई में असली कहानी सीटों की संख्या से ज्यादा उन अतिरिक्त वोटों की है, जिनके लिए दोनों खेमे अंतिम दिन तक राजनीतिक गणित साधेंगे।

एक हजार लीटर दूध बनाने जितना केमिकल, पॉम ऑयल, डिटर्जेंट उपकरण जप्त

100 से अधिक साइबर ठगी में लिप्त 6 ठाों को किया गिरफ्तार



साइबर ठगी कर रहे छह आरोपितों को पकड़ा है। आरोपितों ने शामगढ़ की युवती से 7.50 लाख रुपये ठगे थे। इसकी जांच में पुलिस गिरोह तक पहुंची। अभी तक की जांच में पुलिस ने 11 करोड़ रुपये की ठगी का पता चला है इसमें से 34 लाख रुपये सीज भी कराए गए हैं। अभी तक की जांच में 150 म्यूल खातों की भी जानकारी मिली है जिनका लेन-देन रुकवाया गया है।

एसपी विनोद कुमार मीना ने बताया कि शामगढ़ की एक युवती ने मेट्रोमैनियल साइट पर अपनी फोटो व बायोडेटा भेजा था वहीं से आरोपितों ने उसे निशाना बनाया। उसे पहले अपने प्रेमजाल में फंसाया फिर कहा कि विदेश से गिफ्ट भेजा है जो कस्टम ने पकड़ लिया है उसे छुड़वाने के लिए रुपये देना है जो युवती ने उसके बताए खाते में भेज दिए। फिर इन्हीं आरोपितों ने कस्टम व नारकोटिक्स अधिकारी बनकर फोन किया कि गिफ्ट में मादक पदार्थ है इस तरह डरा धमकाकर लगभग 7.50 लाख रुपये वसूल लिए।

युवती को ठगी का अहसास हुआ तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। एसपी मीना ने इस मामले को लीड किया और लगभग ढाई माह में पूरे गिरोह को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपितों में 26 वर्षीय त्रिलोकी कुमार पुत्र नागेंद्र राऊत, 25 वर्षीय शिवम पुत्र चंद्रेश्वर प्रसाद, 25 वर्षीय बबलू कुशवाह पुत्र मनीष कुशवाह, 29 वर्षीय गुंजन पुत्र चंद्रेश्वर प्रसाद गुप्ता, 24 वर्षीय शशि कुमार पुत्र शंभुप्रसाद कलवार सभी निवासी निवासी भेलाही थाना भेलाही जिला पूर्वी चंपारण (बिहार) व मास्टर माईड 34 वर्षीय टोनी कुमार पुत्र संजय राम निवासी छपिया गोपालगंज (बिहार) को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने इस मामले में अब तक देश भर में 150 म्यूल बैंक खाते सीज कराए हैं। इनमें लगभग 20 लाख रुपये जमा हैं। शेष करीब 15 लाख रुपये वाले खाते भी सीज करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। पुलिस को जो 11 करोड़ रुपये की ठगी का हिसाब मिला है उसमें करीब 150 फजी सिम कार्ड उपयोग होने की आशंका जताई गई।

दिहौी, आगरा, फिरोजाबाद से ली फर्जी सिम
आरोपितों में सभी 12वीं पास या स्नातक हैं। एक टीम म्यूल बैंक अकाउंट एवं म्यूल मोबाइल सिम उपलब्ध कराती हैं। अधिकांश मोबाइल सिम आगरा, फिरोजाबाद, दिल्ली एवं बिहार से ली गई हैं। कुछ मोबाइल सिम एवं बैंक अकाउंट भोपाल के भी हैं। टीम के सदस्य अलग स्थानों और अलग-अलग राज्य में घूमते रहते हैं और निश्चित अंतराल में जगह बदलते हैं। यह टीम खातों में जमा होने वाले रुपये निकालकर दूसरे खातों में जमा करती है।

माही की गूंज, मंदसौर।
मादक पदार्थों की तस्करी का प्रमुख केंद्र मंदसौर जिला अब सिंथेटिक दूध बनाने की फैक्ट्रियों का भी केंद्र बन रहा है। चंबल पार वाले क्षेत्र में अभी तक नकली दूध बनाने की तीन फैक्ट्रियां पकड़ी जा चुकी हैं।
सुवासरा थाने के ग्राम खेजड़िया भूप में एक बाड़े में चल रहे सिंथेटिक दूध की फैक्ट्री पर पुलिस की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। यहां से पुलिस को भारी मात्रा में सिंथेटिक दूध तैयार करने की सामग्री मिली है। इसमें दूध पाउडर के कट्टे, रासायनिक पदार्थ, पाम आयल, डिटर्जेंट सहित अन्य, सामग्री एवं उपकरण शामिल हैं। पुलिस का मानना है कि उपलब्ध सामग्री से लगभग 1 हजार लीटर सिंथेटिक दूध तैयार किया जा सकता था। अभी मौके से कुछ आरोपितों को हिरासत में भी लिया है।
एसपी विनोद कुमार मीना ने बताया कि, सूचना मिलने के बाद सुवासरा थाना प्रभारी सहित पूरी टीम ने ग्राम खेजड़िया भूप में एक घर के पीछे बने बाड़े में छापामार कार्रवाई की। वहां से सिंथेटिक दूध तैयार कर दूर-दूर तक सप्लाई करने की सूचना प्राप्त हुई थी। कार्रवाई के दौरान मौके से दूध पाउडर के कट्टे, हानिकारक केमिकल, पाम आयल के डिब्बे, डिटर्जेंट, मिक्सर एवं नकली दूध तैयार करने में प्रयुक्त अन्य उपकरण बरामद किए हैं। अभी इनकी मात्रा का आंकलन किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन सामग्रियों का इस्तेमाल नकली दूध तैयार करने में किया जा रहा था।

आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर पुलिस का शिकंजा
केमिकल एवं अन्य मिलावटी पदार्थों से तैयार नकली दूध को आसपास के क्षेत्रों में सप्लाय किए जाने की आशंका है। इस तरह का कारोबार आमजन के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। पुलिस ने आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही नकली दूध के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और सप्लाय चेन की भी जांच की जा रही है।



गरोठ के चचावदा चकोटिया, कोटड़ा बुजुर्ग में भी मिल चुकी है फैक्ट्री
पुलिस ने कुछ माह पहले ही गरोठ क्षेत्र के कोटड़ा बुजुर्ग व चचावदा चकोटिया में छापामार कार्रवाई कर सिंथेटिक दूध तैयार करने की फैक्ट्री पर कार्रवाई की थी। गांधीसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में स्थित ग्राम चचावदा चकोटिया में एक बाड़े में सिंथेटिक दूध बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री कास्टिक सोडा, यूरिया, केमिकल, दूध पाउडर सहित अन्य सामग्री जप्त की थी।
मौके पर लगभग 700 लीटर दूध का स्टक भी मिला था। वहीं यहां मिली सामग्री से लगभग 25 हजार लीटर दूध बनाया जा सकता था। मौके से आगरा का निवासी युवक मनीष पुत्र बैजनाथ मिला था जो खुद को केमिस्ट बता रहा था और गांव में ही दिनेश पुत्र मोतीलाल गुर्जर बाड़े को किराये पर लेकर यह फैक्ट्री चला रहा था।
इससे पहले शामगढ़ व गरोठ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कोटड़ा बुजुर्ग में भी एक डेयरी से 2000 लीटर दूध, 200 लीटर केमिकल व दूध के पावडर जैसा पदार्थ मिला था। प्रारंभिक रिपोर्ट में नमूना फेल हो गया था और उसे मानव उपयोग के लिए ठीक नहीं बताया गया था इसके बाद अधिकारियों के आदेश पर वहां सील कर रखा हुआ 2000 लीटर दूध नष्ट कर दिया गया था।

एक घर के अंदर, दूसरा बाहर पहरे पर

माही की गूंज, मंदसौर।
जिले के अंतर्गत आने वाली पिपलियामंडी पुलिस ने ग्राम बालागुढ़ा और उमरिया में दिनदहाड़े सूने मकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाले दो शातिर अंतरराज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण और नकदी समेत 4,62,150 रुपए का मशरूका बरामद किया है। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल बिना नंबर की होंडा शाइन मोटरसाइकिल भी जप्त की है, जक्त की गई बाइक की कीमत करीब 1 लाख रुपए आंकी जा रही है।



मामले में पुलिस का कहना है कि, गिरफ्तार आरोपियों में 38 वर्षीय मिथुन बाबू उर्फ अल्लाफ, पिता नजीर शाह फकीर, निवासी कच्ची बस्ती, नीमचौड़ा, निंबाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ और 40 वर्षीय इजराइल उर्फ कालू मोहम्मद, पिता इस्माइल खान, निवासी पितलवाड़ी कला, थाना छेटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ है। दोनों ही आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं।

48 घंटे में खंगाले 100 से ज्यादा सीसीटीवी
27 सितंबर को बालागुढ़ा में रहने वाले संदीप प्रजापत ने सूने मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी दिन उमरिया में रहने वाले फनालाल मालवीय ने भी ऐसी ही वारदात की शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों मामलों में पिपलियामंडी थाने में पुलिस ने संबंधित थाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। वारदातों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस दोनों इलाकों में 100 से ज्यादा स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने के साथ साइबर सेल मंदसौर से तकनीकी सहायता ली गई। जांच के दौरान मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने महज 48 घंटों के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

15 मिनट में वारदात को अंजाम देकर फरार
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि, आरोपी दिन में मोटरसाइकिल से एमपी और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों के गांवों में घूमते और सूना मकान दिखाई देने पर एक आरोपी ताला तोड़कर घर के अंदर चला जाता है। दूसरा आरोपी बाहर खड़े रहकर घेराव लगाता है। दोनों मिलकर घर में घुसकर चोरी करके फरार हो जाते हैं।

एमपी और राजस्थान में दिया वारदातों को अंजाम
आरोपियों की निशानदेही पर बालागुढ़ा मामले में 2 लाख 50 हजार 130 रुपए और उमरिया मामले में 2 लाख 12 हजार 20 रुपए का चोरी गया मशरूका बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों का अपराधिक रिकॉर्ड भी अपडेट कर दिया है।

चाकूबाज भोला, कालिया और काला को सजा
माही की गूंज, रतलाम।
दो वर्ष पहले मालीकुआ क्षेत्र में दूध विक्रेता को चाकू मारने वाले तीनों आरोपियों भोला उर्फ मोनू पिता रामेश्वर पाटीदार (29) निवासी ग्राम मूंडूड़ा, तहसील-देपालपुर, वर्तमान निवासी पैलैस रोड रतलाम, हितेश उर्फ भय्यू उर्फ कालिया पिता सीताराम साहू (34) निवासी राजीव नगर और विष्णु उर्फ काला पिता आनंद टॉक (22) निवासी हरिजन बस्ती, सिलावटों का वास को न्यायालय ससम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष की सजा व जुर्माने से दंडित किया है।



अनर लोक अभियोजन समर्थ पाटीदार ने बताया कि फरियादी अजय पाटीदार निवासी कुआंझागर ने पुलिस को बताया था कि 16 दिसंबर 2024 की शाम करीब 7 बजे में लोकेन्द्र नाथ मंदिर दूध देने गया था। दूध देकर वापस लौट रहा था, तब भोला पाटीदार का नाबालिक भांजा शराब के नशे में बीच सड़क पर मोबाइल चला रहा था। हॉर्न बजाया तो वह नहीं हट्टा। उसे साइड में होने का कहा तो वह गालियां देने लगा। उसने उसके मामा भोला पाटीदार को फोन लगाया। माली कुआंदेवरे के पास पहुंचा तो कार से भोला पाटीदार उसका भांजा उतरे और चाकू से वार करने लगे। भोला पाटीदार उसके भांजे व अन्य दो साथियों ने बीच-बचाव करने आए विकास गुर्जर, राहुल जाट, अमन माली व रakesh जाट के साथ भी मारपीट की। फिर ये लोग भाग गए। पुलिस ने विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने अभियुक्त भोला पाटीदार, विष्णु उर्फ काला व हितेश को यह सजा सुनाई। भोला और विष्णु पहले से जेल में अन्य प्रकरण में बंद हैं। भोला का भांजा नाबालिक होने से उसका प्रकरण बाल न्यायालय में चल रहा है।

जोश-जोश में विधायक से हुई गलती

माही की गूंज, राजालपुर।
जिले में यातायात नियमों के पालन को लेकर लोगों को जागरूक करने वाले शाजापुर जिले की कालापिपल विधानसभा के भाजपा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी का बाइक चलाते समय दोनों हाथ हैंडल से हटाने का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। सोमवार को कालापिपल से जामनेर जा रही जन सेवा रैली के दौरान बनाए गए वीडियो में विधायक कार्यकर्ताओं के साथ बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। हेलमेट लगाए विधायक कुछ देर के लिए बाइक का हैंडल छोड़कर दोनों हाथ ऊपर उठाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं।
वायरल वीडियो ने खड़े किए सवाल वीडियो सामने आने के बाद पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने विधायक के इस कृत्य पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग को लेकर सवाल किए। चौधरी ने कहा कि आम नागरिकों, खासकर युवाओं और बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने की सीख देनी चाहिए।
कुणाल चौधरी ने विधायक के पूर्व के यातायात जागरूकता से जुड़े प्रसंग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव के दौरान विधायक गणेश प्रतिमा को कार में सीट बेल्ट लगाकर चलाता है तो उसके खिलाफ चालान और कार्रवाई की जाती है, तो क्या जनप्रतिनिधियों के लिए भी वही नियम लागू होंगे? चौधरी ने सवाल किया कि यह यातायात जागरूकता है या स्टंट?



पहले सीट बेल्ट की सीख, अब बाइक पर हाथ छोड़ने का वीडियो
कुणाल चौधरी ने विधायक के पूर्व के यातायात जागरूकता से जुड़े प्रसंग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव के दौरान विधायक गणेश प्रतिमा को कार में सीट बेल्ट लगाकर चलाता है तो उसके खिलाफ चालान और कार्रवाई की जाती है, तो क्या जनप्रतिनिधियों के लिए भी वही नियम लागू होंगे? चौधरी ने सवाल किया कि यह यातायात जागरूकता है या स्टंट?
पहले सीट बेल्ट की सीख, अब बाइक पर हाथ छोड़ने का वीडियो
कुणाल चौधरी ने विधायक के पूर्व के यातायात जागरूकता से जुड़े प्रसंग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव के दौरान विधायक गणेश प्रतिमा को कार में सीट बेल्ट लगाकर चलाता है तो उसके खिलाफ चालान और कार्रवाई की जाती है, तो क्या जनप्रतिनिधियों के लिए भी वही नियम लागू होंगे? चौधरी ने सवाल किया कि यह यातायात जागरूकता है या स्टंट?
पहले सीट बेल्ट की सीख, अब बाइक पर हाथ छोड़ने का वीडियो
कुणाल चौधरी ने विधायक के पूर्व के यातायात जागरूकता से जुड़े प्रसंग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव के दौरान विधायक गणेश प्रतिमा को कार में सीट बेल्ट लगाकर चलाता है तो उसके खिलाफ चालान और कार्रवाई की जाती है, तो क्या जनप्रतिनिधियों के लिए भी वही नियम लागू होंगे? चौधरी ने सवाल किया कि यह यातायात जागरूकता है या स्टंट?

पैसे हड़पने के मामले में आरोपी सपना टाकुर की बढ़ी रिमांड

सपना ने प्रक्रिया चलने की बात कही। 15 जनवरी 2026 को रकम वापस करने के नाम पर मोबाइल पर आया ओटीपी भी उससे लिया गया। इसके बाद वाट्सएप पर ई-स्टॉप की प्रति भेजी गई। रोहित के अनुसार रकम मांगने पर सपना ने उसे धमकाया और झूठे केस में फंसाने की बात कही। समाचार के माध्यम से सपना की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद उसने पुलिस को शिकायत की।

करोड़ों के लेन-देन की जांच
रतलाम में दर्ज मामले में पुलिस रुपेश चपरोत और सपना के बीच हुए करोड़ों रुपये के लेन-देन, संपत्ति की खरीद और पुराने प्रकरणों से जुड़े बिंदुओं की जांच कर रही है। चपरोत ने सपना पर कुल 3 करोड़ 45 लाख 75 हजार 900 रुपये लेने का आरोप लगाया है। इसमें नकद रकम, आरटीजीएस, प्लेट और मकान से संबंधित लेन-देन शामिल हैं।
चपरोत ने पुलिस को बताया था कि विजय लोढ़ा के खिलाफ हंडी की दलाली के नाम पर उसने 11 लाख रुपये दिए थे। रकम वापस दिलाने में मदद के भरोसे पर सपना उसके संपर्क में आई थी। दिसंबर 2025 में सपना ने खुद को मंदसौर की नारकोटिक्स टीआई बताते हुए चपरोत से संपर्क किया था। उसने विजय लोढ़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर की प्रति भी वाट्सएप पर भेजी और मकान व प्लेट की कुर्की सहित कानूनी कार्रवाई करवाकर रकम वापस दिलाने का भरोसा दिया था।

संपत्तियों और रकम के स्रोत की पड़ताल
पुलिस रिकार्ड के अनुसार सपना के खिलाफ औद्योगिक क्षेत्र थाने में पहले से दो प्रकरण दर्ज हैं। वर्ष 2021 में मंदसौर के एक युवक से मेडिकल कॉलेज में एंबुलेंस लगाने के नाम पर चार से पांच लाख रुपये लेने का मामला दर्ज हुआ था। वर्ष 2024 में रतलाम के एक बैंककर्मी को मंदसौर में पेट्रोल पंप खुलवाने का झांसा देकर करीब 15 लाख रुपये लेने का प्रकरण दर्ज हुआ। दोनों मामले न्यायालय में विचारधीन हैं। अन्य मामलों में सपना के अनुसार सपना पति से अलग रह रही है



और 12वीं तक पढ़ी है। पूछताछ में उसने तुलसी लोहार में दो प्लेट होने और दोनों पर मकान निर्माण चलने की जानकारी दी है। उसने साड़ी की दुकान संचालित करने तथा तीवरी के समीप आलनिया फटा क्षेत्र में करीब 25 बीघा कृषि भूमि होने की बात भी बताई है। पुलिस इन संपत्तियों के दस्तावेज, स्वामित्व और इन्हें खरीदने के लिए रकम के स्रोत की जांच कर रही है। पुलिस हनीट्रैप के एंगल से भी जांच कर रही है, हालांकि फिलहाल ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है।
पहले से दो ठगी के मामले
पुलिस रिकार्ड के अनुसार सपना के खिलाफ औद्योगिक क्षेत्र थाने में पहले से दो प्रकरण दर्ज हैं। वर्ष 2021 में मंदसौर के एक युवक से मेडिकल कॉलेज में एंबुलेंस लगाने के नाम पर चार से पांच लाख रुपये लेने का मामला दर्ज हुआ था। वर्ष 2024 में रतलाम के एक बैंककर्मी को मंदसौर में पेट्रोल पंप खुलवाने का झांसा देकर करीब 15 लाख रुपये लेने का प्रकरण दर्ज हुआ। दोनों मामले न्यायालय में विचारधीन हैं। अन्य मामलों में सपना के अनुसार सपना पति से अलग रह रही है

सेटलमेंट किए जाने की जानकारी भी पुलिस की जांच में सामने आई है।

सपना ने आरोपों से किया इन्कार
न्यायालय में पेशी के दौरान सपना टाकुर ने मीडिया के सामने अपने ऊपर लगे आरोपों से इन्कार किया। उसने कहा कि तेजानार स्थित मकान उसने 1 करोड़ 30 लाख रुपये में खरीदा है और उसकी बाकायदा रजिस्ट्री हुई है। उसके अनुसार 20 लाख रुपये आरटीजीएस और 1 करोड़ 10 लाख रुपये नकद दिए गए थे। सपना ने खुद को जबरन फंसाए जाने की बात कही।
उसने यह भी दावा किया कि उपलब्ध रिकार्डिंग में चपरोत की ओर से मकान खाली करने की बात कही जा रही है। सपना ने चपरोत के जीजा कमल मख्खरा पर मकान का कब्जा वापस करने के लिए जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

वन अमले से बचने के लिए चलती पिकअपसे कूदे सागौर तरकर

माही की गूंज, खंडवा।

पुनासा वन परिक्षेत्र के फिफरी जंगल में सागौन की अवैध कटाई की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम ने एक पिकअप वाहन का करीब 10 से 12 किलोमीटर तक पीछा किया। वन अमले से चिरता देख आरोपी मोहन और टेमचा के बीच चलती पिकअप से कूदकर जंगल में फरार हो गए। इसके बाद अनियंत्रित पिकअप सड़क किनारे खेत में पलट गई। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें सागौन के 18 लट्टे मिले।

वन विभाग के अनुसार जब्त सागौन की मात्रा 2.424 घनमीटर है, जिसकी कीमत एक लाख रुपये से अधिक आंकी गई है। मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी रवि सेठ ने बताया कि 29 सितंबर को मुखबिर से दक्षिण फिफरी बीट के जंगल में सागौन की अवैध कटाई की सूचना मिली थी। सूचना पर वन विभाग की टीम ने क्षेत्र की घेराबंदी की। देर रात जंगल की ओर से एक पिकअप आती दिखाई दी। वनकर्मियों ने वाहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने रस्तेार बढ़ा दी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने शासकीय वाहन और मोटरसाइकिलों से पीछा शुरू किया।

करीब 10 से 12 किलोमीटर तक पीछा किए जाने के बाद आरोपियों ने पिकअप की गति धीमी की और चलती गाड़ी से कूदकर जंगल की ओर भाग निकले। इसके बाद चालक के नियंत्रण से बाहर हुई पिकअप सड़क किनारे खेत में पलट गई। वाहन की तलाशी में सागौन प्रजाति के 18 लट्टे बरामद हुए।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि जब्त पिकअप पर अंकित पंजीयन क्रमांक एमपी-47 जेडए-2178 किसी दोपहिया वाहन का है। वन विभाग अब यह पता लगा रहा है कि पिकअप पर दूसरे वाहन का क्रमांक क्यों लगाया गया था और उसका वास्तविक पंजीयन क्रमांक क्या है।

वन विभाग ने पिकअप और सागौन के लट्टे जब्त कर लिए हैं। फरार आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। कार्रवाई में परिक्षेत्र सहायक राजेश सोनारे, वनरक्षक सियाग्राम सिंह, पवन पलासिया, संदीप तिवरोले और ननूलाब बारे शामिल रहे।



युवती से छेड़छाड़, दोस्तों से भी मारपीट युवक पर प्रकरण दर्ज

माही की गूंज, सेधवा।

वीर बलिदानी खाज्या नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित आदिवासी पारंपरिक नवाई कार्यक्रम देखने आई युवती से छेड़छाड़ और उसके दोस्तों से मारपीट का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर सेंधवा शहर थाना पुलिस ने नया बस स्टैंड क्षेत्र निवासी युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। घटना मंगलवार दोपहर करीब 1.30 से 2 बजे के बीच की बताई गई है। युवती की शिकायत पर रात करीब 8.30 बजे प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस के अनुसार ग्रामीण थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती मंगलवार को नवाई कार्यक्रम देखने के लिए गांव से सेंधवा आई थी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले वह किला गेट क्रमांक-2 के पास पाल पर बैठकर दोस्तों का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान नया बस स्टैंड क्षेत्र निवासी जितन

रावल वहां पहुंचा।

युवती ने शिकायत में बताया कि युवक ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। युवती के दोस्त मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव का प्रयास किया। आरोप है कि युवक ने उनके साथ भी गाली-गलौज और मारपीट की।

घटना के बाद युवती अपने दोस्तों के साथ सेंधवा शहर थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। शहर थाना पुलिस के उप निरीक्षक संतोष पाटीदार ने बताया कि शिकायत के आधार पर मंगलवार रात जितन रावल निवासी नया बस स्टैंड, सेंधवा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 296(बी) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।



एडिशनल एसपी का हुआ शाजापुर ट्रांसफर

माही की गूंज, खंडवा।

राज्य शासन द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के तहत एडिशनल पुलिस अधीक्षक (शहर) महेंद्रसिंह तारणेकर को शाजापुर स्थानांतरित किया गया है। शाजापुर में उन्हें एडिशनल पुलिस अधीक्षक के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खंडवा में उनका कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक का हो चुका था। तारणेकर इससे पूर्व भी खंडवा में एडिशनल पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। दोनों कार्यकाल मिलाकर उन्होंने जिले में करीब पांच वर्ष तक अपनी सेवाएं दीं। उनके स्थान पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अमित सिंघारिया को खंडवा में पदस्थ किया गया है। वे अब तक जबलपुर में प्रशिक्षु पुलिस अधिकारी के रूप में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी का दायित्व संभाल रहे थे। स्थानांतरण के बाद वे खंडवा में एडिशनल पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभालेंगे।



जंगल में मादा तेंदुए का मिला शव, बीमारी से मौत की आशंका

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले की ग्राम पंचायत रेहगुन के जंगल में बुधवार को करीब डेढ़ से दो वर्ष की मादा तेंदुए का शव मिला। शव रेहगुन गांव से करीब एक किलोमीटर दूर मिला। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। मौत का वास्तविक कारण शव परीक्षण और प्रयोगशाला जांच की रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा।

ग्रामीणों के अनुसार, रेहगुन निवासी मायाराम ने मंगलवार सुबह करीब 10.30 बजे जंगल में तेंदुए को पड़ा देखा था। उस समय तेंदुआ जीवित दिखाई दे रहा था। दोपहर करीब 3 बजे दोबारा मौके पर पहुंचने पर वह मृत मिला। ग्रामीणों ने शाम करीब 4 बजे वन विभाग को इसकी सूचना देने की बात कही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बाद वन अमला देर से मौके पर पहुंचा।

ग्रामीणों के मुताबिक तेंदुआ पिछले कुछ दिनों से बीमार था और



ठीक से चल नहीं पा रहा था। उनका कहना है कि इसकी जानकारी पहले वन विभाग को भी दी गई थी। ग्रामीणों ने समय पर उपचार या बचाव की व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाया। बड़वानी के उप वनमंडलाधिकारी विजय मोरे ने बताया कि तेंदुए की उम्र करीब डेढ़ से दो वर्ष है। चिकित्सा दल के अनुसार मौत करीब एक दिन पहले हुई है। वन विभाग के अनुसार मंगलवार शाम

करीब 4 बजे एक चरवाहे के माध्यम से तेंदुए की जानकारी मिली थी।

वन परिक्षेत्र अधिकारी सचिन लोवंशी ने बताया कि शव परीक्षण की प्रारंभिक जांच में तेंदुए के बीमार होने और पेट खाली होने की जानकारी सामने आई है। मौत के कारण की अंतिम पुष्टि प्रयोगशाला जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद होगी। वन विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है।

दो सप्ताह बाद भी चोरी का सुराग नहीं, पीड़ित परिवार ने लगाई गुहार

माही की गूंज, सेंधवा। पटेल कॉलोनी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के खंड समन्वयक याकूब मंसूरी के सूनू मकान में 13 सितंबर की रात हुई चोरी के मामले में दो सप्ताह से अधिक समय बीतने के बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। चोरी का सुराग नहीं मिलने से परेशान पीड़ित परिवार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतरसिंह आर्य को आवेदन देकर मामले में

हस्तक्षेप की मांग की है। परिवार ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और चोरी गया सामान बरामद करने की मांग की है। याकूब मंसूरी ने आवेदन में बताया कि उनकी भतीजी की शादी आगामी दिनों में तय है। शादी की तैयारियों और खरीदारी के लिए 13 सितंबर को परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर गए थे। इसी दौरान चोरों ने सूनू मकान को निशाना बनाया और घर में रखे आभूषण व नकदी चोरी कर ले गए। पीड़ित के

अनुसार चोर मकान से करीब 18 तोला सोने के आभूषण, डेढ़ किलो चांदी के जेवरत और 5 से 6 लाख रुपये नकद ले गए। शादी से ठीक पहले हुई चोरी से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। दो सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। परिवार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने, वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज

करने तथा आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस के अनुसार फरियादी की शिकायत और उपलब्ध कराई गई सामान की सूची के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग पुलिस टीमों को लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी।

मरीज के भरोसे का सौदा करने पर हो सख्ती



डॉ. भूषण

स्वीकार कर लेते हैं, यह यकीन करते हुए कि जो इलाज सुझाया जा रहा है, वह जरूरी है और उसका दाम वाजिब है। जब अस्पताल इस मजबूरी का फायदा उठाकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने लगें, तो यह उस भरोसे की बुरी तरह ध्वस्त करने जैसा है।

मध्याह्न खाद्य एवं औषधि प्रशासन का हालिया सर्वे इस समस्या की भयावहता को उजागर करता है। पड़ताल करने वालों ने पाया कि इंटरवेनस (आईवी) इन्फ्यूजन सेट की जो लागत अस्पताल को 11.05 रुपये पड़ती है, उसका दाम मरीज से 325 रुपये वसूला गया—यानी 2,841 प्रतिशत अधिक। 29.41 रुपये में खरीदे गए कैथेटर का अधिकतम खुदरा मूल्य 310 रुपये वसूला गया, जो 954 फीसदी अधिक है। कई तरह के आवश्यक मेडिकल सामानों पर कीमतें बहुधा 2,841 प्रतिशत तक ज्यादा पाई गईं। खाद्य एवं औषधि आयुक्त तुकाराम मुंडे ने डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को पत्र लिखकर केंद्रीय समीक्षा और स्पष्ट नियमों की मांग की है, ताकि खुदरा दाम और घोषित अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच कितने अंतर की अनुमति हो, यह तय किया जा सके।

अस्पताल एक वैध वाणिज्यिक संस्था की श्रेणी में आते हैं। उनके लिए खरीद दाम, साफ-सुथरा भंडारण, पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना और बर्बादी को लागत में जोड़ना एक जरूरत है, और वाजिब मुनाफा कमाने का हक भी है। लेकिन एक टिकाऊ व्यापारिक मुनाफे और मजबूर ग्राहक से ज्यादा पैसे उगाहने के बीच सीमारेखा स्पष्ट है। किसी भी अन्य उद्योग में ऐसा करने पर तुरंत 'विश्वास-भंग' का जुर्माना लग सकता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में, जहां ग्राहक बीमार और डरा हुआ होता है तथा कहीं और तुरंत जा नहीं सकता, इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, जहां अनाप-शनाप दाम वसूलना एक परिपाटी बन जाए, वहां नियामक परामर्श काफी नहीं होते। जो अस्पताल जान-बूझकर ज्यादा कीमत वसूलते हैं, उनके लिए अतिरिक्त लिया गया पैसा मरीजों को वापस लौटाना और भारी जुर्माना भरना अनिवार्य किया जाना चाहिए। बार-बार ऐसा करने वालों को दंड स्वरूप सरकारी स्वास्थ्य बीमा पैनल से बाहर करना और निजी भुगतान नेटवर्क से कुछ समय के लिए निलंबित या फिर स्थायी रूप से काली सूची में डाल देना चाहिए।

हालांकि, हमें कुछ मेडिकल सामानों पर वसूले जाने वाले बहुत ज्यादा मुनाफे को शेष सामान्य वस्तुओं पर भी लागू मानकर, एकमुश्त सख्त दाम नियंत्रक निजाम बनाने की गलती करने से बचना होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में आवश्यक मेडिकल प्रक्रियाओं पर 'कड़ी ऊपरी कीमत' तय करने, तमाम स्टैंडर्ड मेडिकल ऑपरेशनों के लिए पैकेज रेट तय करने और मेट्रो शहरों के अस्पतालों के कमरों का किराया आसपास के श्री-स्टार होटलों के कमरों के किराए के बराबर करने के लिए एक कानूनी संस्था बनाने की सिफारिश की है। बेशक, समिति ने मरीजों की परेशानी को सही ढंग से समझा है, लेकिन उसके सुझाए गए उपायों से स्वास्थ्य तंत्र को भारी नुकसान पहुंचने का खतरा भी है।

आईवी सेट एक मानकीकृत औद्योगिक उत्पाद है, जबकि क्लीनिकल देखभाल वैसी नहीं है। एक ही बीमारी वाले दो मरीजों को उम्र, दिल की बीमारी के इतिहास या सर्जरी की जटिलता के आधार पर एकदम अलग इलाज की आवश्यकता हो सकती है। बीमारी के लिए विशिष्ट विशेषज्ञता



वाले अस्पताल में कई घंटों तक चलने वाली जटिल कैसर सर्जरी की कीमत को उसी तरह से तय नहीं किया जा सकता, जिससे प्लास्टिक कैथेटर की कीमत तय की जाती है। जब सरकारें सख्त और तयशुदा कीमतें लागू कर देंगी, तो दो चीजें होंगी—अगर ऊपरी कीमत बहुत ज्यादा रख दी जाएगी, तो मरीजों को कोई खास बचत नहीं होगी; अगर यह सीमा बहुत कम रखी जाएगी, तो गुणवत्ता प्रभावित होगी। सेवा प्रदाता तब गुणवत्ता से समझौता करने लगेंगे, ज्यादा जोखिम वाले या जटिल मामलों को लेने से मना कर सकते हैं, छिपे हुए चार्ज जोड़ने लगेंगे या आधुनिक तकनीक में निवेश करना रोक देंगे।

आयुषान भारत (पीएम-जय) के लिए ऋय-झंका तैयार करने में कई साल बिताने के बाद, मैंने इस प्रक्रिया को करीब से देखा है। कागज पर कीमत की सीमा तय करना आसान है। यह सुनिश्चित करना कहीं ज्यादा मुश्किल है कि मरीज को उस कीमत पर वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाली, सुरक्षित और सही इलाज मिले। दामों पर एकमुश्त अंकुश लगाने के बजाय, भारत को एक विशेष पांच-सूत्रीय नियामक रणनीति की जरूरत है।

महंगी दवाओं, इम्प्लांट और इस्तेमाल होने वाली चीजों के मामले में होनी चाहिए।

द्वितीय, अनुचित मुनाफे को सही सिद्ध न कर पाने पर सख्ती से कदम उठाएं। स्टैंडर्ड दवाओं, उपकरणों और इस्तेमाल होने वाली चीजों के मामले में नियामकों को असामान्य कीमतों पर लगातार नजर रखनी चाहिए। प्रत्येक उत्पाद की अंतिम कीमत खुद तय करने की बजाय मुनाफे की तार्किक सीमा बांधना, संदर्भ मूल्य और व्यवस्थित कीमत निगरानी तंत्र ज्यादा सही तरीके हैं।

लेकिन नियामक तंत्र असरदार होना चाहिए। जो अस्पताल बार-बार अनुचित चार्ज लगाते पाए जाएं, वहां जुर्माना इतना बड़ा होना चाहिए कि उनकी यह प्रवृत्ति बदल जाए। सरकारी फंड वाली योजनाओं या स्वास्थ्य बीमा नेटवर्क के तहत पैनल में शामिल होना फायदेमंद है। निरंतर गलत इस्तेमाल से यह सुविधा खतरे में पड़ सकती है।

तृतीय, सरकारी और बीमा कंपनियां अपनी थोक ऋय शक्ति का अधिक असरदार ढंग से प्रयोग करें। ज्यादातर बहस इस बात पर होती है कि अस्पताल मरीजों से क्या चार्ज करें। हम इस बात पर बहुत कम ध्यान देते हैं कि अस्पताल और

सरकारी खरीदार खुद दवाओं, डिवाइस और इम्प्लांट के लिए क्या कीमत चुकाते हैं।

थोक खरीद का अनुभव, टाटा मेमोरियल सेंटर बताता है कि बचत की कितनी बड़ी गुंजाइश रहती है। सरकारी योजनाएं करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य देखभाल का खर्च उठाती हैं। इस विशाल ऋय शक्ति का फायदा बेहतर दाम पाने के लिए मोल-भाव करने में उठाना जाना चाहिए।

चतुर्थ, न केवल दाम, बल्कि उपयोगिता को भी नियंत्रित करें। हर सेवा की कीमत होने से अधिक कमाई करने को प्रोत्साहन मिलता है। अधिक टेस्ट, अस्पताल में ज्यादा दिन प्रवास और अतिरिक्त प्रोसीजर से ज्यादा आमदनी होती है, चाहे उससे मरीज की सेहत में सुधार हो या न हो। अगर मरीज को जरूरत ही न हो, तो 20 फीसदी छूट पर हुआ सीटी स्कैन भी बर्बादी ही है। सरकारी खरीदार और बीमा कंपनियों को असामान्य मामलों की पहचान करने के लिए क्लीनिकल पाथवे, मेडिकल ऑडिट और क्लेम सिलॉलिटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए; मसलन, सिजेरियन सेक्शन से बच्चे पैदा करवाने की असामान्य रूप से उच्च दर, लंबे समय तक आईसीयू में रखना, जरूरत से ज्यादा टेस्ट, जांच या किसी खास प्रोसीजर का बार-बार उपयोग। गैर-जरूरी इलाज भी इलाज के बड़े हुए खर्च का उतना ही बड़ा कारण है, जितना कि चीजों की ज्यादा कीमतें।

पंचम, गुणवत्ता को भी दाम की तरह ही साफ तौर पर दर्शाया जाना चाहिए। आज मरीजों को उन अस्पतालों के नतीजों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, जिन्हें वे चुनते हैं। समय-समय पर अस्पतालों को कुछ मानक पैमानों पर अपनी कार्यप्रणाली का लेखा-जोखा प्रदर्शित करना चाहिए, जैसे अस्पताल में इलाज के दौरान लगा संक्रमण, दोबारा भर्ती होने की दर, कुछ खास इलाज के परिणाम और मरीजों का अनुभव।

निस्संदेह, भारत अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत किए बिना निजी स्वास्थ्य तंत्र में कीमतों की समस्या को हल नहीं कर सकता। एक भरोसेमंद सरकारी विकल्प निजी खिलाड़ियों को सही राह पर रखता है।

अस्पतालों को निवेश करने, नए इलाज और वाजिब मुनाफा कमाने की व्यापारिक आजादी होनी चाहिए। लेकिन इस आजादी का मतलब यह नहीं हो सकता कि आईसीयू बिस्तर पर पड़े मरीज का आर्थिक शोषण किया जाए।

पति की हत्या कर पत्नी ने
अधजला शव रेत में दफनाया

माही की गूंज, उदयगढ़।

जिले के थाना उदयगढ़ पर 24 सितंबर को ग्राम ताती, अंबा में पुजारा फलिया से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें फरियादी राहुल द्वारा अपने पिता रामा लगभग पंद्रह दिन से नहीं दिखाई दिया तो उसके लड़के ने पिता की हत्या होने की शंका जाहिर की और अपनी माँ से पिता के बारे में पूछने पर शंका होने पर घर को तलाश किया तो उसके पिता की डेड बॉडी उसके घर के पीछे वाले कमरे में रेत में दफन होना पाई गई। जो शंका उसकी माँ पर ही होने से उसके द्वारा लास को निकाला गया। व पुलिस को खबर दी गई। पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीकृत किया गया एवं वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया।

पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जेबट के मार्गदर्शन में अनुसंधान किया गया और प्रकरण में मृतक रामा वाकला की पत्नी ही प्रकरण में आरोपी पाई गई। जिसमें मृतक की पत्नी नाहजुबाई को गिरफ्तार किया गया। जिसके द्वारा स्वीकार किया गया कि पति द्वारा उसे चरित्र संका कर झगड़ा किया जाता था। इस कारण उसने झगड़े में लट से उसकी हत्या कर दी थी और शव को जलाकर घर के अंदर रेत में गाड़कर छुपा दिया था। काफी जघन्य गंभीर प्रकरण होने से पुलिस द्वारा 1, 1 कड़ी को मिलाकर अनुसंधान किया गया। प्रकरण में मृतक की पत्नी के द्वारा ही हत्या करना पाया जाने से उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल दाखिल कराया गया है।

स्वच्छता कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर किया सम्मान

माही की गूंज, आलीराजपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत जिले में स्वच्छता कार्य से जुड़े कर्मियों के स्वास्थ्य एवं सम्मान को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत नानपुर, आम्बुआ, बरझर एवं सोंडवा में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए।

स्वास्थ्य शिविरों में ग्राम पंचायतों में स्वच्छता कार्य में संलग्न सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चिकित्सकीय दल द्वारा स्वास्थ्य जांच के साथ आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी प्रदान किया गया। इस दौरान स्वच्छता कर्मियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता कर्मियों द्वारा स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में दिए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका सम्मान भी किया गया। स्वच्छता कर्मियों के कार्य की सराहना करते हुए उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सम्मान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जनभागीदारी को बढ़ावा देने के साथ ही स्वच्छता कार्य से जुड़े कर्मियों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता की भावना को सुदृढ़ करना है। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित इन गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता कर्मियों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया।

श्रवण एवं वाक् बाधित व्यक्तियों के लिए कार्यशाला का आयोजन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलीराजपुर के मार्गदर्शन में नालसा (शिक्षा) योजना 2026 के अंतर्गत जिले के श्रवण एवं वाक् बाधित व्यक्तियों को उनके विधिक अधिकारों एवं शासन की कल्याणकारी योजनाओं एवं विधिक सेवाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से «अंगूज से उद्घोष» विषयक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा ऑडिटोरियम हॉल से किया गया। कार्यशाला में न्यायमूर्ति अल्पेश वाई. कोगजे मुख्य न्यायाधीश म.प्र. उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक म.प्र.रा.वि.से.प्रा., न्यायमूर्ति विवेक रुसिया प्रशासनिक न्यायाधीश म.प्र. उच्च न्यायालय एवं कार्यवाहक अध्यक्ष म.प्र.रा.वि. से.प्रा. एवं न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल न्यायाधीश म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा भी संबोधित किया गया।

सर्वप्रथम प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय एवं हरिश ओहरिया जिला मुख्याधिकार संघ आलीराजपुर एवं सी.डब्ल्यू.एस.एन. छात्रावास ग्राम-कुण्ड के छात्रों द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा का पूजन-माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यशाला का आयोजन म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा वचुंअल मोड के माध्यम से किया गया, जिसका प्रसारण उपस्थित व्यक्तियों को ए.डी.आर. भवन के मीटिंग हॉल में दिखाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तियों को म.प्र. राज्य प्राधिकरण से प्राप्त सेशन प्लान अनुसार विभिन्न विषयों पर प्रश्नोत्तरों द्वारा वचुंअल माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई।

उक्त कार्यक्रम में नंदराम परमार प्रथम जिला न्यायाधीश, आर. पी. सेवेतिया द्वितीय जिला न्यायाधीश, जय पाटीदार सचिव ज.वि.से.प्रा., अनुरागसिंह सुमन जेएमएफसी, अंशुल चन्द्रा जेएमएफसी, सुश्री आंचल जायसवाल जेएमएफसी, श्रीमती शक्ति रावत जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं जिले के श्रवण एवं मूकबाधित व्यक्ति एवं बच्चे उपस्थित रहे।

ग्राम पंचायत की उदासीनता से स्ट्रीट
लाइटें बंद, सफाई व्यवस्था भी बदहाल

ग्रामीणों में नाराजगी, सार्वजनिक शौचालयों में गंदगी और दुर्गंध से राहगीर परेशान

माही की गूंज, उदयगढ़।
खलील मंसूरी

जिले के उदयगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत उदयगढ़ में बुनियादी सुविधाओं की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत की उदासीनता के चलते गांव में स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से बंद पड़ी हैं। वहीं, सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई नहीं होने और नालियों की बदहाल स्थिति के कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

रात्रि में अंधेरे में डूब जाती हैं सड़कें

ग्रामीणों के अनुसार, ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगी स्ट्रीट लाइटें पिछले 15 से 20 दिनों से बंद पड़ी हैं। रात के समय गांव की सड़कों और गलियों में अंधेरा छाया रहता है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि अंधेरे के कारण चोरी जैसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत से जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइटें चालू करवाने की मांग की है।

सार्वजनिक शौचालयों की सफाई नहीं होने से परेशानी

गांव में सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई व्यवस्था भी सवाल के घेरे में है। ग्रामीणों का आरोप है



कचरा वाहन की व्यवस्था पर भी उठे सवाल

कि कई महीनों से शौचालयों की नियमित सफाई नहीं करवाई गई है। स्थिति यह है कि यहां गंदगी, कचरा और शराब की खाली बोतलें पड़ी रहती हैं। शौचालयों से उठने वाली दुर्गंध के कारण इनका उपयोग करना भी मुश्किल हो गया है।

उदयगढ़ आने वाले यात्रियों को सार्वजनिक शौचालय तलाशने में परेशानी होती है। वहीं, शौचालय मिल जाने पर भी गंदगी और बदबू के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है।

नालियों की सफाई और पेयजल व्यवस्था पर भी सवाल

ग्रामीणों के अनुसार, गांव में नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से जगह-जगह गंदगी जमा हो रही है। कई स्थानों पर नालियों के निर्माण और सफाई की समस्या बनी हुई है। इसके अलावा नल-जल योजना के तहत पर्याप्त पेयजल नहीं मिलने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें किसी बड़ी सुविधा की मांग नहीं है। वे केवल नियमित नाली सफाई, स्वच्छ पेयजल, सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई

और रात के समय रोशनी जैसी बुनियादी सुविधाएं चाहते हैं। इसके बावजूद इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।

सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था पर भी उठे सवाल

ग्राम पंचायत की सफाई व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने कर्मचारियों की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सफाई कर्मचारी समय पर सफाई नहीं करते और शिकायतों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता।

ग्रामीणों के अनुसार, सफाई कर्मचारियों को कथित तौर पर मात्र 3,000 से 4,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेदारियों को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की कमी बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सफाई कर्मचारियों को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी जाए और नियमित निगरानी की जाए, तो गांव की सफाई व्यवस्था में सुधार हो सकता है।

कचरा वाहन की व्यवस्था पर भी उठे सवाल

ग्रामीणों ने गांव में कचरा संग्रहण की व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत में कचरा संग्रहण के लिए अलग से व्यवस्थित वाहन की कमी है। वर्तमान में कचरा ले जाने के लिए

ट्रैक्टर का उपयोग किए जाने की बात सामने आई है, जिसे ग्रामीणों ने सरपंच से संबंधित बताया है।

ग्रामीणों के अनुसार, गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग एकत्रित करने तथा उसका उचित निपटान करने की कोई प्रभावी व्यवस्था दिखाई नहीं देती। कचरा उठाने और परिवहन की उचित व्यवस्था नहीं होने से गांव में जगह-जगह गंदगी फैलने की समस्या बनी हुई है।

ग्रामीणों ने की समस्याओं के निराकरण की मांग

ग्राम पंचायत उदयगढ़ के ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि गांव में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को तत्काल चालू करवाया जाए, सार्वजनिक शौचालयों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए, नालियों की सफाई एवं आवश्यक निर्माण कार्य करवाए जाएं तथा नल-जल योजना के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित करने, उनकी नियमित निगरानी करने और गीले-सूखे कचरे के उचित संग्रहण एवं निपटान की व्यवस्था बनाने की मांग भी की गई है।

अब देखा यह होगा कि ग्राम पंचायत उदयगढ़ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी ग्रामीणों को इन समस्याओं को कितनी गंभीरता से लेते हैं और कब तक गांव की मूलभूत सुविधाओं में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं।

इंदौर-दाहोद रेल लाइन परियोजना की बढ़ी रफ्तार

माही की गूंज, धार।

इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना के टीही-पीथमपुर हिस्से में निर्माणाधीन 2.95 किलोमीटर लंबी टीही सुरंग अब निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच गई है। 26 सितंबर 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार सुरंग में कुल 2957 मीटर में से 2551 मीटर बैलास्टलेस ट्रेक (बीएलटी) का काम पूरा हो चुका है।

अब केवल 406 मीटर का कार्य शेष है। इस तरह सुरंग के करीब 86 प्रतिशत हिस्से में ट्रेक का महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो चुका है। सुरंग की लाइनिंग पहले ही पूरी हो चुकी है और अब शेष हिस्से में ट्रेक के साथ

फिनिशिंग कार्यों को गति दी जा रही है।

2551 मीटर में ट्रेक का काम पूरा

सुरंग निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण चरणों में शामिल बैलास्टलेस ट्रेक का काम तेजी से आगे बढ़ा है। 2957 मीटर लंबी सुरंग में 2551 मीटर हिस्से में बीएलटी पूरा हो चुका है। शेष 406 मीटर में ये कार्य किया जाना है। ट्रेक का ये चरण पूरा होने के बाद सुरंग को रेल परिचालन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जुड़े अन्य कार्यों को पूरा किया जाएगा।

लाइनिंग पूरी, ड्रेनेज और कंक्रीट कार्य भी आगे

रिपोर्ट के अनुसार सुरंग की

लाइनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। सुरंग के बाहर ड्रेनेज से जुड़े कार्य में 510 मीटर खोदाई पूरी हो चुकी है। वहीं पीसीसी, रिडनफोर्सेमेंट, राफ्ट कंक्रीट और प्रथम लिफ्ट की वाल कंक्रीट का काम 308 मीटर तक पूरा दर्ज है। शेष हिस्से में ड्रेनेज की दूसरी और अंतिम लिफ्ट सहित अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे हैं।

बैकफिल कंक्रीट का भी अधिकांश काम पूरा

सुरंग से जुड़े बैकफिल कंक्रीट का काम भी काफी आगे बढ़ चुका है। रिपोर्ट में 1800 घनमीटर में से 1523 घनमीटर बैकफिल कंक्रीट पूरा बताया गया है। इसी तरह कट एंड कवर पी-1 हिस्से में 23 हजार घनमीटर में से 22,200 घनमीटर

फिलिंग का कार्य पूरा हो चुका है। इससे इस हिस्से का भी अधिकांश निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है।

रेस्क्यू शाफ्ट और वेंटिलेशन का काम भी प्रगति पर

सुरंग की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े निर्माण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। रेस्क्यू शाफ्ट की 23 में से 17 लिफ्ट में रिडनफोर्सेमेंट का काम पूरा हो चुका है, जबकि 16 लिफ्ट में फार्मवर्क और कंक्रीट का काम पूरा है। स्टेयरकेस वाल की 22 में से 15 लिफ्ट तथा वेंटिलेशन डक्ट बाक्स की 22 में से 15 लिफ्ट का काम पूरा हो चुका है।

पोर्टल-2 का निर्माण पूरा

सुरंग के पोर्टल-2 हिस्से में रिडनफोर्सेमेंट, फार्मवर्क और कंक्रीट

से जुड़े सभी 18 लिफ्ट के कार्य पूरे दर्ज हैं। इससे सुरंग के प्रवेश-निकास से जुड़े निर्माण का ये महत्वपूर्ण हिस्सा भी पूरा हो चुका है।

अंतिम 406 मीटर पर निगाह

अगस्त में पश्चिम रेलवे की जानकारी में भी सुरंग की लाइनिंग पूरी होने और बैलास्टलेस ट्रेक का कार्य तेजी से आगे बढ़ने की जानकारी सामने आई थी। अब 406 मीटर बीएलटी तथा इससे जुड़े फिनिशिंग कार्य पूरे होने के साथ टीही सुरंग का निर्माण एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच जाएगा। इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के इस हिस्से में सुरंग का काम पूरा होना परियोजना की आगे की प्रगति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एआई पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्था की आवश्यकता

माही की गूंज, झाबुआ।

नियंत्रण से बाहर जाकर एआई अब स्वयं से काम कर रहा है, एआई के बढ़ते प्रभाव और इसके नियंत्रण से बाहर होने की संभावित खतरों का मामला संयुक्त राष्ट्र के समक्ष पहुंच चुका है। बीते बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में दिग्गज एआई निर्माताओं ने कहा है हमने एआई बना तो दिया किंतु एआई के नियंत्रण के बाहर होने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि एआई का उपयोग गलत दिशा में हुआ या किया गया तो इससे सम्पूर्ण समाज में बहुत बड़ी उथल-पुथल हो सकती है। ऐसे में एआई की बढ़ती क्षमता मानवता के लिए वरदान है या इसका नियंत्रण से बाहर होना मानवता के लिए अभिशाप साबित हो सकता है।

विश्व में जब भी कोई नई तकनीक विकसित की गई तब वह अपने साथ नई संभावनाएं, नए सपने लाई और अपने क्षेत्र में उस नई तकनीक ने पुरानी समस्याओं के नए समाधान सामने प्रस्तुत किए। परंतु वह विकसीत हुई नई तकनीक अपने साथ कुछ भय और कुछ समस्या भी साथ लाती है। जब कंप्यूटर आया तब अपवाह बनी और लोगों में डर आया कि, नौकरियां चली जाएगी। वर्तमान में एआई के आने पर भी लोगों में यही भय बना है कि, एआई मानवता के लिए खतरा बन सकता है। जैसे मोबाइल ने संचार के माध्यम से लोगों को

आपस में जोड़ा पर बहुत से लोगों ने उसका गलत उपयोग करते हुए मोबाइल को भ्रामक और गलत जानकारी फैलाने का साधन बनाया।

जिस तरह मोबाइल का उपयोग अच्छे और बुरे दोनों कार्यों के लिए किया गया उसी तरह एआई का उपयोग भी अच्छाई और बुराई दोनों के लिए संभव है। एआई मानव सभ्यता की ऐतिहासिक तकनीक है जो स्वयं सोचने समझने की शक्ति रखती है। हाल ही में एआई के गलत उपयोग और हैकिंग के जो मामले सामने आए हैं जिससे समाज में डर का बढ़ गया है, परंतु कुछ हादसों के कारण पूरी तकनीकी क्रांति को रोकने के लिए लामबंद होना समझदारी नहीं हो सकती। इससे उपयुक्त उपाय यह हो सकता है कि, एआई के ऐसे नियम और व्यवस्था बनाई जाए जिसका उपयोग समाज की भलाई के लिए हो।

इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में यही दिखाया गया है कि, इसके सही और उचित उपयोग से हम कैसे विश्व स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। एआई का विकास बहुत तेज है और वैश्विक स्तर पर है, अमेरिका और चीन की कम्पनियां इसमें आगे हैं और जब अमेरिका में एआई द्वारा स्वतः ही हैकिंग कर ली गई तब विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की जिसके बाद सभी ने इसके रोकथाम को लेकर आवाज उठाई। कंपनी प्रमुखों द्वारा एआई के खतरे गिनाते लगे, यह बात



भी सामने आने लगी कि एक दशक में एआई एजेंट सभी को मार सकते हैं। अमेरिका की दोनों दिग्गज कंपनियां एंथ्रोपिक और ओपनएआई के प्रमुखों के अलावा गूगल, स्पेसएक्स, मेटा, एमेजन, और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के एआई प्रमुखों ने भी एआई विकास की गति पर लगाम कसने और कड़ी नियामक व्यवस्था बनाने के लिए अपील की है।

चीन को लगता है कि, अमेरिकी एआई कंपनियां चीन की दिग्गज एआई कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए बेलागम होते एआई

एजेंटों का भय दिखाकर अपनी सरकारों को नियामक व्यवस्था का ऐसा जाल बुनने को उकसा रही है, जिसमें उन्हें तो मनचाही छूट मिले और विदेशी एआई कंपनियों पर सुरक्षा के बहाने प्रतिबंध लग जाएं। चीन की आशंका गलत भी नहीं है, क्योंकि अमेरिकी कंपनी विकास की गति धीमी करने और लांच से पहले एआई एजेंटों की सुरक्षा जांच कराने की बात तो कर रही है पर किसी स्वतंत्र जांच संस्था की बात नहीं कर रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एआई पर लगी हुई इस पूंजी से कमाई करके दिखाना है तो एआई कंपनियों को

दौड़ में आगे रहना होगा। जो स्वतंत्र नियामक संस्थाओं के कड़े सुरक्षा नियमों के चलते संभव नहीं होगा। इसलिए भय दिखाकर अमेरिका स्वयं ही नियामक बन जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ओपनएआई की प्रयोगशाला में जिस डैकॉग की घटना ने भयभीत किया जिसे लेकर विश्व में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा दिया है कि, एआई भविष्य में मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा बनेगी या नहीं? इसका स्पष्ट उत्तर हां या ना में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि एआई स्वयं में खतरनाक नहीं है, असल समस्या यह है कि, मानव इसे किस तरह से विकसीत करते हैं और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे एक चिकित्सक एआई का उपयोग रोगों का पता लगाने उसके उचित उपाय में उपयोग करता है वहीं गलत उपयोगकर्ता एआई का उपयोग गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने में कर सकते हैं। हमें उन लोगों को रोकना होगा जो एआई का उपयोग गलत कर सकते हैं। जैसे बिजली के आने से पूरे विश्व में कार्य करने का तरीका बदल दिया, और उसने ढ़ांचों में भी परिवर्तन किया, इसी तरह एआई भी सभी स्थानों पर उपस्थित होकर लोगों में परिवर्तन को लाने में सक्षम होगा।

हालांकि चीन की आशंका सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है परंतु भारत का भविष्य जिम्मेदार एआई से सुरक्षित हो सकता है।



रिक्तेस वैरागी

फटियर और परम बुद्धिमान एआई एजेंटों को लांच न कर सके। भारत जैसे देश में आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार, की चुनौतियां हैं वहां एआई एक वरदान साबित हो सकता है। एक बच्चा जो स्कूल नहीं जा पाता वह मोबाइल पर एआई से पढ़ सकता है। एक किसान अपनी उजब बढ़ा सकता है, व्यापार की व्यवस्थाओं में सुधार लग सकता है। एक युवा स्टार्टअप खड़ा कर सकता है। बहरहाल, खतरा यह नहीं कि एआई आने वाले समय में घातक हो जाएगी, बल्की असली खतरा मानव की लापरवाही ही सामने आएगी। एआई को रोकने नहीं उसे जिम्मेदार बनाने के बारे में भी विचार करना चाहिए, सुरक्षा संस्था के गठन के साथ-साथ जिसके लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा कार्म्यक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवाहों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422